

पीएम मोदी ने युवा उद्यमियों को दिया प्रेरणादायी संदेश



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवा उद्यमियों की लगातार बढ़ती सफलता की सराहना की और कहा कि उनका दृढ़ संकल्प तथा समर्पण स्टार्टअप क्षेत्र में नए-नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। उन्होंने इसे 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने वाली सबसे बड़ी ताकत करार दिया।

पीएम मोदी ने एक्स संदेश में एक प्राचीन संस्कृत सुभाषित का भी उल्लेख किया

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स संदेश में एक प्राचीन संस्कृत सुभाषित का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, "दुर्लभान्यपि कार्याणि सिद्ध्यन्ति प्रोद्यमेन हि। शिलाऽपि तनुतां याति प्रपातेनार्णसो मुहुः।" इसका अर्थ है कि अत्यंत कठिन और दुर्लभ कार्य भी लगातार उद्यम (परिश्रम) से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बार-बार गिरने वाली पानी की बूंदें कठोर शिला (पत्थर) को भी धीरे-धीरे क्षीण कर देती हैं और उसमें छेद कर देती हैं।

सुभाषित के माध्यम से युवाओं को दिया यह संदेश

प्रधानमंत्री ने इस सुभाषित के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया कि असंभव लगने वाले लक्ष्य भी निरंतर मेहनत, जोश और जुनून से हासिल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा शक्ति ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का मुख्य आधार बनेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर आगमन, एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया आत्मीय स्वागत



जयपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर पहुंचीं। जयपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राष्ट्रपति महोदया का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्रीगण दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. वंदा, एवीएम.एम. बंदोपाध्याय, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, जिला कलेक्टर जयपुर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

गंगासागर मेले का सफल समापन, 1.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान



पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24-परगना जिले में आयोजित गंगासागर मेले का समापन हो चुका है। इस मेले में 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक बयान में कहा कि एक छोटी सी आग लगने की घटना को छोड़कर गंगासागर मेला बिना किसी अप्रिय घटना के खत्म हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कुछ जगहों से गंगासागर मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने की कोशिशों की जा रही हैं, जो हाल ही में बिना किसी अप्रिय घटना के खत्म हुआ है, सियाव एक छोटी सी आग लगने की घटना के जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।" पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा, "देश भर से लाखों तीर्थयात्रियों के इस सालाना जमावड़े को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 15000 पुलिसकर्मियों की टीम ने सैकड़ों सीनियर अधिकारियों की देखरेख में काम किया। सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से और मजबूत किया गया था, जिसमें 1,300 से ज्यादा सीसीटीवी और थर्मल-इमेजिंग ज़ोन शामिल थे।" पोस्ट में आगे लिखा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि राज्य में सभी त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों। गंगासागर मेले के बारे में राज्य के मंत्री अरूप बिस्वास ने कहा, "यह सब प्लान मुख्यामंत्री ममता बनर्जी ने तैयार किए थे। हम उनकी तरफ से काम करते रहे। गुरुवार तक 1 करोड़ 30 लाख लोग आए। मुख्यामंत्री ने हर समय निगरानी रखी।" बता दें कि गंगासागर मेला कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक मेला माना जाता है। देशभर से श्रद्धालु हर साल मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान करने के लिए यहां आते हैं। पवित्र गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम को गंगासागर कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह धार्मिक मेला हर साल मकर संक्रांति के मौके पर पश्चिम बंगाल के गंगासागर में कपिल मुनि के आश्रम में लगता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर उकसाया, US-ताइवान के बीच 250 अरब डॉलर का समझौता

नई दिल्ली (एजेंसी)। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अब ऐसा कदम उठाया है, जिससे चीन के नाराज़ होने की पूरी आशंका है। अमेरिका ने गुरुवार को ताइवान के साथ एक बड़े व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के जरिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में चीन के दबदबे को सीधी चुनौती देने की कोशिश की गई है। समझौते के तहत अमेरिका ताइवान से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा, जबकि इसके बदले ताइवान अमेरिका में 250 अरब अमेरिकी डॉलर का नया निवेश करेगा। अमेरिका ने इस करार को ऐतिहासिक व्यापार समझौता बताया है और कहा है कि इससे देश के सेमीकंडक्टर उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान से आयात होने वाले सामान पर 32 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिसे बाद में घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। नए समझौते के तहत टैरिफ को और कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, जो जापान और दक्षिण कोरिया पर लगाए गए शुल्क के बराबर है।



अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ताइवान के साथ यह समझौता एक मजबूत आर्थिक साझेदारी की नींव रखेगा। इसके तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में कई विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। वहीं ताइवान सरकार ने भी बयान जारी कर समझौते की पुष्टि की और कहा कि इससे

दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और मजबूत होगा। इससे पहले अमेरिका ने पिछले महीने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार, सैन्य उपकरण और सेवाएं बेचने की मंजूरी दी थी। इस पैकेज में जेवेलिन मिसाइल सिस्टम, एल्टियस-700एम और एल्टियस-600 मानवरहित हवाई वाहन, एएच-1 डब्ल्यू सुपरकोबरा हेलीकॉप्टरों के स्पेर पार्ट्स, हिमार्स मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एम107ए7 सेल्फ-प्रोपेल्ल आर्टिलरी यूनिट्स और टीओडब्ल्यू एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। अमेरिका के इन कदमों से चीन पहले ही बेहद नाराज़ रहा है। हथियार सौदे के बाद चीन ने कई अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। अब ताइवान के साथ हुआ यह विशाल व्यापार और निवेश समझौता ड्रेगन की बचेनी की और बढ़ा सकता है।

घातक वायरस से लड़ने के लिए गुजरात में बनेगी पहली BSL-4 लैब



गुजरात। गुजरात अपनी जैव-सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में पहली बार बायोसेफ्टी लेवल-4 (BSL-4) लैब बनाई जाएगी, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और अत्यधिक संक्रामक वायरस पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होगी। यह हार्ड-सिक्वोरिटी लैब वैक्सीन विकास, तेज जांच प्रणाली और जानलेवा वायरसों पर शोध में मदद करेगी, जिनका अभी कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। यह कदम हाल के वर्षों में सामने आए कोरोना जैसी महामारी और पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरों को देखते हुए उठाया गया है। कोरोना महामारी के दौरान देश को पुणे स्थित एकमात्र BSL-4 लैब पर निर्भर रहना पड़ा था। वहीं गुजरात में चांदीपुरा वायरस और लम्पी स्किन डिजीज जैसे मामलों के सामने आने से राज्य में उच्च स्तर की लैब की जरूरत और बढ़ गई थी। यह नई BSL-4 और एनएसए BSL-4 (ABSL-4) लैब गांधीनगर के सेक्टर-

मंदिर परिसर में खजाने की तलाश करेगी कर्नाटक सरकार

-युक्त को मिले सोने के आभूषणों के बाद लिया गया फैसला

कर्नाटक। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने गडग जिले में खजाने की खोज के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, लक्कुंडी गांव में एक मकान के निर्माण के दौरान सोने के आभूषण मिलने के बाद राज्य सरकार ने ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत के लिए प्रसिद्ध लक्कुंडी स्थित कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर खुदाई कराने का फैसला किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर परिसर में संभावित खजाने की तलाश के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीनें, ट्रक और ट्रैक्टर तैनात किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि खुदाई के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्र को चिन्हित कर आधिकारिक खुदाई क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "इस काम में 15 महिलाओं और पांच पुरुषों को लगाया गया है।" यह मामला उस समय सामने आया, जब एक युवक को मकान निर्माण के दौरान तांबे का एक बर्तन मिला। जब उस बर्तन को खोला गया तो उसके अंदर सोने के आभूषण पाए गए। माना जा रहा है कि ये आभूषण करीब 300 से 400 वर्ष पुराने हैं। युवक ने ईमानदारी दिखाते हुए सभी आभूषण जिला प्रशासन को सौंप दिए, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका सोने, चांदी, हीरे, मोती, माणिक, मूंगे और लहसुनिया जैसे बहुमूल्य खनिजों से समृद्ध माना जाता है। खुदाई से जुड़े सूत्रों के अनुसार, "लक्कुंडी ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध केंद्र रहा है और उपलब्ध प्रमाण संकेत देते हैं कि यहां आज भी जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में कीमती संपदा छिपी हो सकती है।" गौरतलब है कि नवंबर 2024 में भी लक्कुंडी में हुई एक खोज के दौरान भारतीय नागरिकों के बीच प्रभावी उपयोग कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऊर्जा, कौशल और आधारभूत सुविधाओं में ठोस बदलाव किया गया है।



रुचि और बढ़ गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इलाके के विभिन्न हिस्सों से अब भी नीलम, मोती, रत्न, हीरे और लहसुनिया जैसे कीमती पत्थर मिलने की सूचनाएं मिल रही हैं। इतिहास के पन्नों में लक्कुंडी का खास स्थान रहा है। यहां कभी चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल, कलचुरी और विजयनगर शासकों का शासन रहा था। इस निर्माण के दौरान तांबे का एक बर्तन मिला। जब उस बर्तन को खोला गया तो उसके अंदर सोने के आभूषण पाए गए। माना जा रहा है कि ये आभूषण करीब 300 से 400 वर्ष पुराने हैं। युवक ने ईमानदारी दिखाते हुए सभी आभूषण जिला प्रशासन को सौंप दिए, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका सोने, चांदी, हीरे, मोती, माणिक, मूंगे और लहसुनिया जैसे बहुमूल्य खनिजों से समृद्ध माना जाता है। खुदाई से जुड़े सूत्रों के अनुसार, "लक्कुंडी ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध केंद्र रहा है और उपलब्ध प्रमाण संकेत देते हैं कि यहां आज भी जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में कीमती संपदा छिपी हो सकती है।" गौरतलब है कि नवंबर 2024 में भी लक्कुंडी में हुई एक खोज के दौरान भारतीय नागरिकों के बीच प्रभावी उपयोग कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऊर्जा, कौशल और आधारभूत सुविधाओं में ठोस बदलाव किया गया है।

मुंबई में कांग्रेस का फ्लॉप प्रदर्शन, मगर महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार की बढ़ी मुश्किलें

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों और रुझानों ने प्रदेश की राजनीति में शक्ति संतुलन की नई तस्वीर पेश की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बड़े अंतर से सबसे ताकतवर दल बनकर सामने आई है, जबकि कांग्रेस की स्थिति मिली-जुली दिखाई दे रही है। मुंबई जैसे बड़े महानगरों में कांग्रेस कमजोर साबित हुई, लेकिन राज्यभर के कुल आंकड़ों में उसने ठाकरे और शरद पवार जैसे क्षेत्रीय नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। 29 नगर निगमों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भाजपा 910 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 213 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस 171 सीटों के साथ आगे बढ़ी है। भाजपा से काफी पीछे रहने के बावजूद कांग्रेस राज्य की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है, जो ठाकरे और शरद पवार के गुटों के लिए चिंता का संकेत है। चौकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कुल प्रदर्शन में मुंबई (BMC) का योगदान लगभग शून्य रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई और शिक्षा के प्रमुख केंद्र पुणे—दोनों जगह कांग्रेस केवल 5-5 सीटों पर ही बढ़त बना सकी। पिंपरी-चिंचवाड़, वसई-विरार, उल्हासनगर, नांदेड़ वाघाला, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले और कल्याण-डोंबिवली जैसे अहम इलाकों में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। मुख्यमंत्री शिंदे के गढ़ ठाणे में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आगे है, जबकि नवी मुंबई में उसका प्रदर्शन शून्य रहा।



जहां कांग्रेस ने मारी बाजी

भले ही बड़े शहरों में भाजपा का दबदबा रहा हो, लेकिन कुछ नगर निगमों में कांग्रेस ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। लातूर में पार्टी 21 वार्डों में बढ़त लेकर सबसे आगे है। अमरावती और चंद्रपुर में कांग्रेस क्रमशः 13 और 12 वार्डों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। भिवंडी निजामपुर में भी कांग्रेस 12 वार्डों में बढ़त लेकर अन्य दलों से आगे निकल गई है। इसके अलावा नागपुर (22 वार्ड), कोल्हापुर (23 वार्ड) और अकोला (15 वार्ड) में पार्टी दूसरे स्थान पर मजबूती से टिकी हुई है।

पवार और ठाकरे का गिरता ग्राफ

चुनावी रुझानों ने क्षेत्रीय नेताओं के लिए सख्त संकेत दिए हैं। एनसीपी के अरुन्धती संघर्ष में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। शरद पवार गुट का असर अब सीमित क्षेत्रों तक सिमटता दिख रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई में तो मुकबले में है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में उसकी स्थिति कांग्रेस और एनसीपी (अजीत गुट) से भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है।

ईरान की स्थिति पर नजर, अपने लोगों के लिए जरूरी कदम उठाएंगे: भारत

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत, ईरान में तेजी से बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और देश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें छात्र, व्यावसायिक लोग, पेशेवर, तीर्थयात्री और नाविक शामिल हैं। उन्होंने कहा, "स्थिति को देखते हुए हमने कुछ सलाह जारी की हैं। सभी भारतीय नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने का अनुरोध किया गया है और जो भारतीय पहले से ईरान में हैं, उन्हें उपलब्ध साधनों से, जिनमें वाणिज्यिक उड़ानें शामिल हैं, देश छोड़ने की सलाह दी गई है। हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने नागरिकों की भलाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।" ईरान में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ में गंभीर आर्थिक परिस्थितियों, जैसे कि रिकॉर्ड स्तर की मुद्रास्फूर्ति और मुद्रा पतन, के कारण शुरू हुए और अब पूरे देश में फैल गए हैं। प्रदर्शनकारी राजनीतिक और शासन संबंधी बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। 5 जनवरी को भारत ने अपने

न करने का अनुरोध किया गया है और जो भारतीय पहले से ईरान में हैं, उन्हें उपलब्ध साधनों से, जिनमें वाणिज्यिक उड़ानें शामिल हैं, देश छोड़ने की सलाह दी गई है। हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने नागरिकों की भलाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।" ईरान में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ में गंभीर आर्थिक परिस्थितियों, जैसे कि रिकॉर्ड स्तर की मुद्रास्फूर्ति और मुद्रा पतन, के कारण शुरू हुए और अब पूरे देश में फैल गए हैं। प्रदर्शनकारी राजनीतिक और शासन संबंधी बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। 5 जनवरी को भारत ने अपने



ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी खजाना विभाग ने एक पत्र जारी किया था जिसमें चाबहार पोर्ट के लिए शर्तीय प्रतिबंध छूट की गाइडलाइन दी गई थी, जो 26 अप्रैल 2026 तक मान्य है। हम इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के साथ संपर्क में हैं।" पिछले साल, अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर संचालन जारी रखने के लिए छह महीने की प्रतिबंध छूट दी थी, जो 29 अक्टूबर से प्रभावी थी। 2024 में भारत और ईरान ने शाहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए 10 साल का समझौता किया था। हालांकि, अमेरिकी विदेश

सचिव ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर-प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत दी गई प्रतिबंध छूट को 29 सितंबर से रद्द कर दिया, जिससे चाबहार पोर्ट या अन्य संबंधित गतिविधियों में संचालन लोगों पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो सकते थे। इसके बावजूद भारत अप्रैल तक बिना किसी डंडात्मक कार्रवाई के टर्मिनल का विकास और संचालन जारी रख रहा है। यह बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित करता है और पाकिस्तान को पार किए बिना व्यापार और कनेक्टिविटी की सुविधा देता है।

योगी सरकार की योजनाओं से गांवों में बदली तस्वीर, गांव-गांव तक पहुंचा विकास

यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार आकांक्षामक विकास खंडों की तस्वीर बदलने में पूरी लगन से जुटी है। विकास अब कागजों तक सीमित न रहकर गांवों की जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई पिछड़े और आकांक्षामक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन राशि का प्रभावी उपयोग कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऊर्जा, कौशल और आधारभूत सुविधाओं में ठोस बदलाव किया गया है।

पिछड़े क्षेत्र बना रहे प्रेरणादायी विकास मॉडल

इन प्रयासों का नतीजा यह है कि जो क्षेत्र कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझते थे, वे अब प्रेरणादायी विकास मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। स्पष्ट है कि योगी सरकार ने आकांक्षामक ब्लॉकों को परिणाम आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है।

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार पर जोर

विकास खंडों को मिल रही प्रोत्साहन राशि से व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बरेली के मझगांव विकास खंड में दो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की रचनात्मक क्षमता और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए एस्ट्रोनीमी लैब का निर्माण कराया गया है। इससे ग्रामीण बच्चों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का अवसर मिला है।

ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय और खेल सुविधाएं

न्याय पंचायत गैनी में छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए पुस्तकालय का निर्माण कराया गया। वहीं मझगांव (बरेली) के ग्राम पंचायत बेहटा बुजुर्ग में शारीरिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए मिनी स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण किया गया है। यह पहल ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ने के साथ नशामुक्त और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है।



बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर विशेष फोकस

प्रोत्साहन राशि का प्रभावी उपयोग बढ़ावू के वजीरगंज विकास खंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी देखने को मिला। वहीं छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीसी रोड और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया, जो 'बेटी की सुरक्षा और शिक्षा' को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की सोच को दर्शाता है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा

इसी तरह बलिया के सोह्राव विकास खंड में विकास खंड कार्यालय भवन पर 10 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया गया है। इससे न केवल बिजली खर्च में कमी आई है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में ग्रीन एनर्जी मॉडल को भी बढ़ावा मिला है।

स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास में लक्षित निवेश

आकांक्षी ब्लॉकों में स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल, मानव संसाधन विकास और कौशल उन्नयन जैसे क्षेत्रों में लक्षित निवेश किया गया है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों से जुड़े संकेतकों पर विशेष ध्यान देते हुए योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ताकि सामाजिक विकास के साथ मानव विकास सूचकांक में भी सुधार हो सके।

सुशासन और पारदर्शिता का दिख रहा है

दशाता है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा

इसी तरह बलिया के सोह्राव विकास खंड में विकास खंड कार्यालय भवन पर 10 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया गया है। इससे न केवल बिजली खर्च में कमी आई है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में ग्रीन एनर्जी मॉडल को भी बढ़ावा मिला है।

स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास में लक्षित निवेश

आकांक्षी ब्लॉकों में स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल, मानव संसाधन विकास और कौशल उन्नयन जैसे क्षेत्रों में लक्षित निवेश किया गया है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों से जुड़े संकेतकों पर विशेष ध्यान देते हुए योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ताकि सामाजिक विकास के साथ मानव विकास सूचकांक में भी सुधार हो सके।

सुशासन और पारदर्शिता का दिख रहा है

असर

आकांक्षी विकास खंडों में नजर आ रहा यह परिवर्तन योगी सरकार के सुशासन, पारदर्शिता और निगरानी आधारित मॉडल का परिणाम है। यहां प्रोत्साहन राशि का उपयोग केवल निर्माण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि स्थानीय लाभ, सामुदायिक भागीदारी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है।

देश के लिए बनता दिख रहा है रोल मॉडल

आज उत्तर प्रदेश के ये आकांक्षी ब्लॉक यह संदेश दे रहे हैं कि यदि सरकारी धन सही योजना, ईमानदार क्रियान्वयन और स्पष्ट विजन के साथ खर्च हो, तो वही क्षेत्र प्रेरणादायी विकास की मिसाल बन सकता है। योगी सरकार का यह मॉडल अनिच्छित समय में न सिर्फ प्रदेश, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनता दिख रहा है।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

क्या पैक्स सिलिका चीन का विकल्प बनेगा?

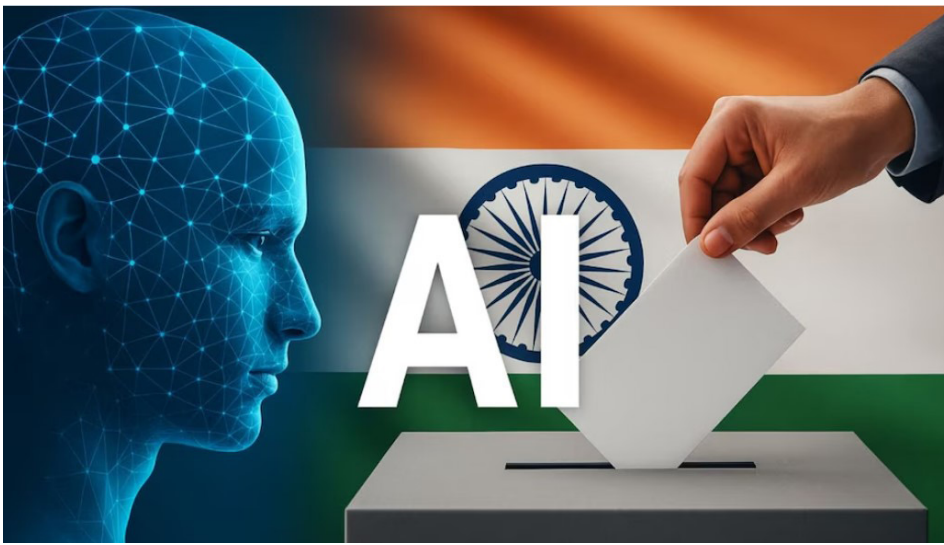
चीन द्वारा जापान को रेयर-अर्थ की सप्लाई रोकने के ताज़ा फैसले ने वैश्विक ट्रेड और रणनीतिक संतुलन को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में यह सवाल तेज़ हो गया है कि क्या दुनिया चीन पर इतनी गहराई से निर्भर रह सकती है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने आठ भरोसेमंद देशों के एक नए संगठन पैक्स सिलिका की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है। यह संगठन सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से खड़ा किया जा रहा है। असल मकसद है रेयर-अर्थ और हाई-टेक सेक्टर में चीन की लगभग एकछत्र चौधराहट को चुनौती देना। रेयर-अर्थ एलिमेंट्स आज की दुनिया की रीढ़ बन चुके हैं। लैपटॉप, एलईडी टीवी, विंड टरबाइन, जेट इंजन, इलेक्ट्रिक वाहन, एमआरआई मशीन और यहां तक कि आधुनिक हथियार प्रणालियों में भी इनका इस्तेमाल होता है। समस्या यह है कि दुनिया की करीब 90 प्रतिशत रेयर-अर्थ सप्लाई चीन के नियंत्रण में है। अमेरिका भले ही तकनीक में आगे हो, लेकिन कच्चे माल के मामले में वह चीन पर निर्भर है। यही मजबूरी अमेरिका को नए विकल्प तलाशने के लिए धकेल रही है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि चीन की आर्थिक और ट्रेड ताकत को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा अब 100 अरब डॉलर तक

पहुंच गया है, जो उसके ट्रेड इतिहास में सबसे ऊंचा स्तर है। दूसरी ओर चीन का ट्रेड सरप्लस 1.20 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। यह स्थिति तब है, जब डोनाल्ड ट्रम्प के दौर में चीन पर असाधारण टैरिफ लगाए गए थे और अमेरिकी बाज़ार तक उसकी पहुंच सीमित करने की कोशिश की गई थी। सच यह है कि अमेरिका को चीन का निर्यात कुछ हद तक घटा जरूर है, लेकिन उसकी भरपाई चीन ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में अपनी पकड़ मजबूत करके कर ली। पिछले दो-तीन दशकों में चीन को दुनिया "सस्ते माल की फैक्ट्री" के रूप में देखती रही है। बल्ब, खिलौने, टॉय, बैटरी सेल, दवाइयां और छोटी मूर्तियों से लेकर रोज़मर्रा की अनगिनत चीज़ें चीन से आती थीं। लेकिन अब चीन की तस्वीर बदल चुकी है। वह सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बैटरी, रेयर-अर्थ प्रोसेसिंग, आधुनिक हथियार प्रणालियां और यहां तक कि अपने एआई मॉडल्स भी दुनिया को बेच रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उसने आक्रामक तरीके से कदम बढ़ाए हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में कई पारंपरिक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में पैक्स सिलिका जैसे संगठन की अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चीन का वास्तविक विकल्प बन पाएगा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के पास संसाधन और क्षमता जरूर है, लेकिन सप्लाई चेन विकसित करने में समय, भारी निवेश और राजनीतिक स्थिरता चाहिए।

2029 का चुनाव 'एआई' के नाम पर फेक न्यूज़, डीपफेक और इन्फ्लुएंसर्स के बीच भारतीय लोकतंत्र की कठिन परीक्षा

-डिजिटल प्रचार, एआई कंटेंट और कमजोर नियमन कैसे चुनावी विमर्श और मतदाता व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं

अगर 2019 को भारत का पहला 'व्हाट्सएप चुनाव' कहा गया, 2024 को 'डिजिटल-फॉरवर्ड चुनाव' की संज्ञा दी गई, तो 2026 के विधानसभा चुनाव इन दोनों का मिला-जुला स्वरूप बनकर सामने आ रहे हैं। और अब जो संकेत मिल रहे हैं, वे बताते हैं कि 2029 का आम चुनाव संभवतः भारत का पहला 'एआई चुनाव' होगा—जहां मतदाता, मुद्दे और नैरेटिव, तीनों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की गहरी छाया होगी। आज से लगभग दस हफ्तों के भीतर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव केवल सरकारें नहीं तय करेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि भारत का लोकतंत्र डिजिटल युग की इस तेज़ रफ्तार दौड़ में कितना सजग, कितना सुरक्षित और कितना स्वतंत्र रह पाता है। मीडिया और राजनीति का एक उत्सुक विद्यार्थी होने के नाते, इस बदलते परिदृश्य पर कुछ बुनियादी सवाल पूछना और उनके जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है।



बेलगाम पीट-पत्रकारिता कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पांच 'W' और चुनावी फेक न्यूज़ पत्रकारिता की परंपरा हमें सिखाती है कि किसी भी मुद्दे को समझने के लिए पांच बुनियादी सवाल पूछे जाएं—क्या, कौन, क्यों, कब और कहाँ। चुनावों पर फेक न्यूज़ के असर को समझने के लिए भी यही तरीका कारगर है।

फेक न्यूज़: बेलगाम पीट-पत्रकारिता का नया अवतार
फेक न्यूज़ कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन डिजिटल दौर में इसका दायरा और असर दोनों बेकाबू हो चुके हैं। भारत में इस शब्द की अब तक कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ई-सेप्टी कमिश्नर के अनुसार, फेक न्यूज़ वे मनगढ़ंत सूचनाएं हैं जिन्हें किसी खास राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर गढ़ा और फैलाया जाता है। आज की फेक न्यूज़ केवल गलत सूचना नहीं है; यह रणनीति, हथियार और व्यवसाय—तीनों बन चुकी है। सनसनी, उर और नफरत के सहारे टीआरपी, क्लिक और वोट—तीनों बटोरे जा रहे हैं। इसे

नहीं रहा; पढ़ा-लिखा, शहरी और युवा वर्ग भी इसके दायरे में है। **क्यों?** फेक न्यूज़ भारतीय चुनावों की एक संरचनात्मक विशेषता बन चुकी है। भले ही वोट आज भी ऑफलाइन डाले जाते हों, लेकिन उनकी लड़ाई अब तेज़ी से ऑनलाइन लड़ी जा रही है। भारत में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर हैं। ऐसे में कुछ ही क्लिक में धारणाएं बनाना, भावनाएं भड़काना और नैरेटिव गढ़ना बेहद आसान हो गया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और साइबरपीस के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार, भारत में फैलने वाली कुल फेक न्यूज़ में से 46 प्रतिशत राजनीतिक प्रकृति की होती है। यानी चुनावी राजनीति अब सूचना युद्ध (Information Warfare) का मैदान बन चुकी है।

कब? चुनाव नज़दीक आते ही फेक न्यूज़ अपने चरम पर पहुंच जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2019 के चुनावी वर्ष में फेक न्यूज़ से जुड़े मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की

वृद्धि दर्ज की गई। **कहां?** डिजिटल प्लेटफॉर्म—खासकर सोशल मीडिया—फेक न्यूज़ के सबसे बड़े वाहक हैं। एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं जो भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करे, चाहे वह सच हो या झूठ। छेड़छाड़ किए गए वीडियो, एआई-जनरेटेड तस्वीरें और फर्जी ऑडियो—ये सब तथ्य और कल्पना के बीच की दीवार को तोड़ते जा रहे हैं। **टीवी बनाम डिजिटल: बदलता मीडिया परिदृश्य**

भारत में आज लगभग 100 निजी टीवी चैनल हैं, जिनमें से करीब आधे न्यूज़ चैनल हैं। टीवी की पहुंच आज भी गहरी है—देश के लगभग 23 करोड़ घरों में टेलीविजन मौजूद है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल माध्यम की ओर साफ झुकाव देखने को मिला है। खासकर युवा मतदाता अब खबरें टीवी से कम और मोबाइल स्क्रीन से ज़्यादा हासिल करता है। यही वह जगह है जहां नियंत्रण, संपादन और जवाबदेही की पारंपरिक व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं। **इन्फ्लुएंसर्स: राजनीति का नया**

रेड कॉरिडोर के सिमटने की कहानी: माओवादी हिंसा से विकास और सुरक्षा के संतुलित भारतीय मॉडल तक की सफलता यात्रा

-दमन नहीं, विकास और शासन की पहुंच ने भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौती से उबार

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में भारत के सामने जो सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती खड़ी हुई, वह थी माओवादी या नक्सलवादी विद्रोह। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे देश के लिए "सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती" करार दिया था। उस दौर में तथ्याकथित 'रेड कॉरिडोर' का दायरा लगातार फैल रहा था। 2013 तक यह संकट 126 जिलों तक पहुंच चुका था। लेकिन आज तस्वीर काफी बदली हुई है। यह रेड कॉरिडोर सिमटकर महज 11 जिलों तक रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि आने वाले कुछ महीनों में यह विद्रोह पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। यह बदलाव केवल सैन्य या पुलिस कार्रवाई का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी, बहु-आयामी और परिष्कृत रणनीति का परिणाम है। **माओवादी आंदोलन की जड़ें** माओवादी आंदोलन को समझने के लिए हमें इसके सामाजिक और आर्थिक आधार को समझना होगा। इसकी जड़ें भूमिहीनता, आर्थिक वंचना और सामाजिक हाशियकरण में छिपी हैं। खासकर देश के दूर-दराज के, जंगलों और खनिज संसाधनों से भरपूर इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय दशकों से सरकारी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से वंचित रहे। भूमि अधिकारों की अस्पष्टता, जंगलों पर पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी और विकास परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन ने गहरी नाराजगी को जन्म दिया। इन्हीं हालातों में जमींदारों और स्थानीय ताकतवर वर्गों के खिलाफ किसान आंदोलनों ने हिंसक रूप लेना शुरू किया। धीरे-धीरे यह असंतोष माओवादी विचारधारा से जुड़ गया। माओवादियों ने चीनी क्रांति से प्रेरित "जनयुद्ध" की रणनीति अपनाई, जिसमें ग्रामीण इलाकों को आधार बनाकर शहरों को घेरने की अवधारणा शामिल थी। 2004 में विभिन्न माओवादी गुट एकजुट होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) यानी सीपीआई

(माओवादी) के रूप में सामने आए। उ न क ा विद्रोह। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे देश के लिए "सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती" करार दिया था। उस दौर में तथ्याकथित 'रेड कॉरिडोर' का दायरा लगातार फैल रहा था। 2013 तक यह संकट 126 जिलों तक पहुंच चुका था। लेकिन आज तस्वीर काफी बदली हुई है। यह रेड कॉरिडोर सिमटकर महज 11 जिलों तक रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि आने वाले कुछ महीनों में यह विद्रोह पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। यह बदलाव केवल सैन्य या पुलिस कार्रवाई का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी, बहु-आयामी और परिष्कृत रणनीति का परिणाम है। **माओवादी आंदोलन की जड़ें** माओवादी आंदोलन को समझने के लिए हमें इसके सामाजिक और आर्थिक आधार को समझना होगा। इसकी जड़ें भूमिहीनता, आर्थिक वंचना और सामाजिक हाशियकरण में छिपी हैं। खासकर देश के दूर-दराज के, जंगलों और खनिज संसाधनों से भरपूर इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय दशकों से सरकारी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से वंचित रहे। भूमि अधिकारों की अस्पष्टता, जंगलों पर पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी और विकास परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन ने गहरी नाराजगी को जन्म दिया। इन्हीं हालातों में जमींदारों और स्थानीय ताकतवर वर्गों के खिलाफ किसान आंदोलनों ने हिंसक रूप लेना शुरू किया। धीरे-धीरे यह असंतोष माओवादी विचारधारा से जुड़ गया। माओवादियों ने चीनी क्रांति से प्रेरित "जनयुद्ध" की रणनीति अपनाई, जिसमें ग्रामीण इलाकों को आधार बनाकर शहरों को घेरने की अवधारणा शामिल थी। 2004 में विभिन्न माओवादी गुट एकजुट होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) यानी सीपीआई

दमन नहीं, विकास और शासन की पहुंच ने भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौती से उबार

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ले जा रहे काफिले पर हमला हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मारे गए। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि समस्या केवल कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती है। तत्कालीन यूपीए सरकार को यह एहसास हुआ कि सिर्फ दमन से इस विद्रोह को खत्म नहीं किया जा सकता। जरूरत एक ऐसे 'नए नजरिये' की थी, जो सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ उन आर्थिक और सामाजिक शिकायतों को भी दूर करे, जिनसे माओवादी आंदोलन को ताकत मिल रही थी। **2014 के बाद बदली रणनीति** 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद माओवादी चुनौती से निपटने की रणनीति को और धार दी गई। इस रणनीति का मूल मंत्र था—"सुरक्षा और विकास साथ-साथ"। सरकार ने इसे केवल बंदूक की लड़ाई नहीं माना, बल्कि शासन की पहुंच और भरोसे की बहाली का अभियान बनाया। सबसे पहले पुलिस और अर्धसैनिक बलों की क्षमताओं को मजबूत किया गया। आधुनिक हथियार, बेहतर संचार प्रणाली, ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया। उग्रवाद-रोधी अभियानों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, पहले से दुर्गम रहे इलाकों में सैफ्टी नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए। इससे सुरक्षाबलों की स्थायी मौजूदगी सुनिश्चित हुई और माओवादियों के तथ्याकथित सुरक्षित ठिकाने सिमटने लगे।



नेटवर्क पर प्रहार और नेतृत्व का कमजोर होना
सुरक्षा बलों ने केवल निचले स्तर के केंद्र को निशाना बनाने के बजाय माओवादियों के संगठनात्मक ढांचे पर प्रहार किया। उगाही नेटवर्क, अवैध खनन और अन्य वित्तीय स्रोतों को तोड़ने की कोशिशें तेज की गईं। केंद्रीय और क्षेत्रीय नेतृत्व को पकड़ने या निष्क्रिय करने से संगठन की कमर टूटती गई। जैसे-जैसे माओवादी दबाव में आए, उनकी आवाजही सीमित होती गई। जंगलों में उनकी मुवमं पर नजर रखने के लिए तकनीकी बेहतर इस्तेमाल हुआ। कई शीर्ष नेता या तो मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए। **विकास और कल्याण की भूमिका**
सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई से स्थायी शांति संभव नहीं थी। सरकार ने यह भी समझा कि अगर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो असंतोष फिर सिर उठा सकता है। इसलिए फिर माओवादी प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, सीधे लाभ हस्तांतरण, राशन, आवास और रोजगार कार्यक्रमों को इन इलाकों में सैफ्टी नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए। इससे सुरक्षाबलों की स्थायी मौजूदगी सुनिश्चित हुई और माओवादियों के तथ्याकथित सुरक्षित ठिकाने सिमटने लगे।

295 रुपये से शुरू होकर संकटों, विवादों और रणनीतिक बदलावों से गुजरती ब्रिटानिया कैसे बनी भारत की शीर्ष एफएमसीजी दिग्गज कंपनी

-नेतृत्व संकट, कोर्ट-कचहरी और प्रतिस्पर्धा के बावजूद नवाचार और लचीलापन बना ब्रिटानिया की असली ताकत

भारत की एफएमसीजी इंडस्ट्री में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रिटानिया उन्हीं नामों में से एक है। बिस्किट के साथ सुबह की चाय, बच्चों का टिफिन, लंबी यात्राओं का साथी—ब्रिटानिया हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। लेकिन इस चमकदार सफलता के पीछे संघर्ष, विवाद, नेतृत्व संकट और अस्तित्व पर मंड़राते खतरे की एक लंबी कहानी छिपी है। 295 रुपये के मामूली निवेश से शुरू हुई यह कंपनी आज करीब 1.42 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ देश की शीर्ष एफएमसीजी कंपनियों में गिनी जाती है। **1992 का यादगार विज्ञापन और ब्रांड की भावनात्मक पकड़** 1992 के दौर में ब्रिटानिया का एक विज्ञापन बेहद लोकप्रिय हुआ, जिसके अंत में कहा जाता था—"Have a Good Day!" यह लाइन सिर्फ एक साइन-ऑफ नहीं थी, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। लंबे समय तक चलने वाले इस विज्ञापन ने ब्रांड को उपभोक्ताओं के ज़ेहन में स्थायी जगह दिला दी। यही वह दौर था जब ब्रिटानिया केवल बिस्किट बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद घरेलू नाम बन चुकी थी। **130 साल का सफर: एक संक्षिप्त परिचय**

ब्रिटानिया भारत की सबसे पुरानी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1892 में कोलकाता में हुई थी, जब ब्रिटिश व्यवसायियों के एक समूह ने 'Britannia Biscuit Company' के नाम से एक छोटी फेक्ट्री शुरू की। उस समय कुल निवेश मात्र 295 रुपये था। यह तथ्य आज भी भारतीय उद्योग जगत में प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया जाता है। 1938 में नालिन चंद्र सेन गुप्ता ब्रिटानिया के पहले भारतीय चेयरमैन बने। इसके बाद कंपनी का स्वामित्व भारतीय हाथों में आता गया। एक समय यह कंपनी 'V.S. Brothers' के नियंत्रण में भी रही और 'Britannia Biscuit Company (V.S. Brothers)' के नाम से जानी गई। **'बिस्किट किंग' से संकट के दौर तक**

एक समय ब्रिटानिया को 'बिस्किट किंग' कहा जाता था। लेकिन 1990 के दशक में कंपनी को ऐसे झटके लगे, जिनसे उ स क ि अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। 1993 से 2009 के बीच ब्रिटानिया ने बार-बार गंभीर उतार-चढ़ाव देखे। ये संकट सिर्फ बाजार या बिज्जी से जुड़े नहीं थे, बल्कि बॉर्डरूम, मालिकाना हक, ट्रेडमार्क और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े थे। निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा था और बाजार में यह चर्चा तक होने लगी थी कि शायद यह ऐतिहासिक कंपनी बंद न हो जाए।

तीन बड़े विवाद जिन्होंने हिला दी कंपनी **1993: 'बिस्किट राजा' राजन पिल्लई का पतन** 1990 के दशक की शुरुआत में ब्रिटानिया के तत्कालीन चेयरमैन राजन पिल्लई पर फंड की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे। कंपनी दो गुटों में बंट गई—एक पिल्लई समर्थक और दूसरा प्रमोटर नुरुली वाडिया के नेतृत्व वाला समूह। मामला अदालत तक पहुंचा और मैनेजमेंट पूरी तरह से पंगु हो गया। यह ब्रिटानिया के इतिहास का पहला बड़ा झटका था। **2003-2005: तीडरशिप का महा-संकट** इस दौर में तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर को वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते अचानक पद छोड़ना पड़ा। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट लगभग खाली हो गया। न कोई



स्पष्ट उत्तराधिकारी था, न कोई दीर्घकालिक रणनीति। यह समय ब्रिटानिया के लिए अत्यंत अनिश्चितता भरा था। **2006-2009: फ्रांसीसी साझेदार के साथ बॉर्डरूम वॉर** ब्रिटानिया और फ्रांसीसी कंपनी डैनीन (Danone) के बीच गंभीर विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगे कि डैनीन ने 'टाइगर' ब्रांड को चुपके से दूसरे देशों में अपने नाम से रजिस्टर कर लिया। यह मामला करीब तीन साल तक कोर्ट में चला। इस दौरान कंपनी की ऊर्जा और फोकस कानूनी लड़ाई में उलझा रहा। **सबसे गंभीर संकट: जब अस्तित्व पर ही सवाल उठा**

1990 का दशक ब्रिटानिया के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। चेयरमैन पर लगे आरोपों, कोर्ट-कचहरी के मामलों और अंदरूनी कलह ने कंपनी को लगभग ठप कर दिया। निवेशकों का भरोसा टूटने लगा। पहली बार यह आंशका खुलकर सामने आई कि कहीं यह 100 साल पुरानी कंपनी इतिहास न बन जाए। **हर संकट से उबरने की रणनीति** डैनीन के साथ साझेदारी और राजन पिल्लई की विदाई नुरुली वाडिया ने फ्रांसीसी कंपनी डैनीन के साथ रणनीतिक साझेदारी कर बॉर्डरूम में संतुलन बदला। राजन पिल्लई को बाहर किया गया और कंपनी में पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा मिला। 1997

को किए गए, जिनमें किसी नेता की आवाज़ को इस तरह तैयार किया गया कि वह सीधे मतदाता से बात करता हुआ लगे। इन्हीं चुनावों के दौरान, मेटा (फेसबुक-इंस्टाग्राम) ने मुसलमानों और एक प्रमुख विपक्षी नेता के खिलाफ हिंसा के आह्वान वाले 14 एआई-जनरेटेड चुनावी विज्ञापनों को मंजूरी दे दी। यह तथ्य अपने-आप में चौंकाने वाला और डराने वाला है। **चुनाव आयोग: अपेक्षाएं और हकीकत**

इतने गंभीर खतरे के बावजूद, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते हैं। डीपफेक, एआई-जनरेटेड कंटेंट और मॉडर्न-टार्गेटिंग को नियंत्रित करने के लिए सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश अब तक सामने नहीं आए हैं। हाल ही में जिस तरह से एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया, उसने भी आयोग की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं। लगता है कि हम चुनाव आयोग से शायद वह अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए उसे अब तक न तो पर्याप्त कानूनी ताकत दी गई है और न ही तकनीकी संसाधन। **2029: क्या यह सचमुच 'एआई का चुनाव' होगा?**

अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो 2029 का चुनाव—एआई-जनरेटेड भाषणों, पर्सनलाइज्ड प्रोपेगैंडा, डीपफेक बहसों और एल्गोरिदम-निर्देशित मतदाता व्यवहार से तय होगा। यह तकनीक अपने-आप में न तो अच्छी है, न बुरी। सवाल इसका नियमन, पारदर्शिता और जवाबदेही का है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो केवल तकनीक से नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार, मीडिया साक्षरता और नागरिक चेतना से ही रास्ता निकलेगा।



राजीविका महिलाएं विकास की मुख्यधारा में जुड़कर हो रही सशक्त, परिवार को भी बना रही आत्मनिर्भर - भजनलाल शर्मा

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। राजस्थान में भी राजीविका के माध्यम से महिलाएं प्रदेश के विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका की प्रत्येक बहन पारिवारिक आय बढ़ाने में योगदान दे रही है और पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बना रही है। शर्मा शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती और शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना की जाती है। ये तीनों ही रूप हमारी माता-बहनों में समाहित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आवास से लेकर रसोई गैस सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ महिलाओं को प्रदान कर रही है।

महिलाएं - बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी भी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के निर्माण में भी आधी आबादी की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजीविका की

लगभग 13 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से मिलेनियर दीदी भी बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी हैं। साथ ही, महिलाओं ने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति पाई है।

32 हजार ग्राम संगठन के माध्यम से बना राजीविका का मजबूत नेटवर्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 51 लाख ग्रामीण परिवारों को 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। साथ ही, 32 हजार ग्राम संगठन और 1 हजार से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से राजीविका का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि राजीविका संवर्धन के अंतर्गत लगभग 36 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं।

आजीविका संवर्धन के लिए 2 हजार करोड़ रुपये
शर्मा ने कहा कि राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि आजीविका संवर्धन हेतु प्रदान की गई। उन्होंने



कहा कि कृषि एवं पशुपालन और गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साढ़े 3 हजार से अधिक उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से लगभग 3 लाख परिवारों को कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों में जोड़ा गया है। किसान परिवार की महिलाएं पशुपालन भी करती हैं। इसलिए हमारी सरकार पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दे रही है।

2 लाख 26 हजार महिलाओं को मिला निःशुल्क सोनोग्राफी का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना में देय राशि

1 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया गया है। इस योजना में लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मा वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 2 लाख 26 हजार महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है। साथ ही, शिक्षा सेतु योजना के तहत 90 हजार से अधिक महिलाओं व बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह राज्य में महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर उनका प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

एक लाख पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। 1 लाख 44 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, 12 जनवरी को युवा दिवस पर इस वर्ष में 1 लाख पदों की भर्ती परीक्षाओं का

कैलेण्डर जारी किया है। इनमें मातृशक्ति को भी रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवा नीति जारी की है। महिलाएं स्वरोजगार के लिए इसका लाभ उठाएं।

बजट के लिए महिलाओं के सुझाव महत्वपूर्ण
शर्मा ने कहा कि राजीविका की महिलाओं ने बैंक, बाजार और सरकारी योजनाओं से जुड़कर वित्तीय आत्मनिर्भरता पाई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने घर का बजट तो तय करती ही हैं, राजस्थान के बजट में भी वे अमूल्य सुझाव देती हैं। राजीविका महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को भी मजबूत बनाने, आजीविका के नए अवसर पैदा करने, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने, प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित राय दें। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, स्टेट मिशन निदेशक स्वयं सहायता समूह श्रीमती नेहा गिरि सिंह सहित अन्य अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में राजीविका महिलाएं उपस्थित रहीं।

राजस्थान को टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में तेजी से कार्य

-मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बोले—केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं प्रयास

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपरिल पॉलिसेली-2025 लागू की गई है। इस पॉलिसेली में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल्स और वस्त्र विनिर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्र भी इस नीति का हिस्सा हैं। वस्त्र और परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव सहित कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में टेक्सटाइल इन राजस्थान विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा राजस्थान का टेक्सटाइल हब है। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट



पॉलिसेली के तहत भीलवाड़ा, बालोतरा, कोटा, पाली, बाड़मेर जिलों के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम श्यामी राव ने बताया कि राजस्थान में न्यू एज फाइबर की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में मिल्क वीड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस पौधे से प्राप्त फाइबर का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में किया जा सकता है। इस पहल से नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही, इससे उद्योग में नवाचार को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार न्यू एज फाइबर सहित टेक्सटाइल

क्षेत्र में अन्य नवाचारों की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है।

राज्य में 1,800 से अधिक टेक्सटाइल और अपरिल यूनिट्स-
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार कारीगरों और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और वित्तीय सहायता दे रही है। इससे इस क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ ही बड़े उद्योग सशक्त होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजस्थान में टेक्सटाइल सेक्टर में आधुनिक तकनीक और उत्पादन तरीकों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान के वस्त्र उद्योग के सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रोड मैप तैयार कर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 1,800 से अधिक टेक्सटाइल और अपरिल यूनिट्स कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात बढ़कर 13,500 करोड़ रुपये हो गया है। बैठक में उद्योग वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी कांग्रेस - दिगराज सिंह

-मनरेगा बचाओ अभियान के तहत शाहपुरा विधानसभा में किसान कांग्रेस का

जन-जागरण कार्यक्रम

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। देश के गरीब, मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब निर्णायक संघर्ष की राह पर है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को कमजोर करने और मजदूरों के हक छीनने की साजिश के विरोध में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में किसान कांग्रेस द्वारा "मनरेगा बचाओ अभियान" के तहत विशाल जन-जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव - अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, दिगराज सिंह शाहपुरा के नेतृत्व में किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया और मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलावों का खुलकर विरोध किया। सभा को संबोधित करते



हुए दिगराज सिंह शाहपुरा ने कहा— "मनरेगा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों गरीब मजदूरों की जीवनरेखा है। सरकार जानबूझकर इस योजना को कमजोर कर रही है ताकि गरीबों से उनका रोजगार छीना जा सके। किसान पार्टी मनरेगा के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी।" उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान में देरी, काम के दिनों में

कटौती और ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर गरीब मजदूरों को योजना से बाहर करने की साजिश रची जा रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को मनरेगा के अधिकारों की जानकारी दी गई और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। दिगराज सिंह शाहपुरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलाव वापस नहीं लिए तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर उपस्थित रहे।

मकर संक्रांति पर सार्थक पहल एडवोकेट दिनेश शर्मा का मार्मिक संदेश

सादिक हिन्दस्तानी
सांगानेर (रॉयल पत्रिका)। राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यवेक्षण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के सांगानेर विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा की मार्मिक अपील गोवंश को अकाल मृत्यु से बचाए और मनचाहा पुण्य प्राप्त करें। पुण्य करना हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा कार्य माना गया है। पुण्य कई तरीके से किया जाता है। मकर संक्रांति पर हमारे बहुत सारे भाई बंधु पुण्य कमाने के नाम पर एक ही दिन में सुबह से शाम तक ठूस-ठूस कर गोवंश को हरा चारा, सूखा चारा, गुड, दलिया, चना और भी न जाने क्या-क्या खिलाकर पुण्य कमाने का कार्य करेंगे। पूरे इंडिया का उस दिन का उेटा कलेक्ट करके देखना सबसे ज्यादा गोवंश की मौतें उस वीक में सबसे ज्यादा होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भूखे प्यासे बड़बान गोवंश को क्षमता से ज्यादा एक ही दिन

संक्रांति के बाद तक प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा खिलाएं जिससे गोवंश पर लेती है। जैसे अकाल होना, आतें फटना, पेट खराब होना जैसी बीमारियों से तड़प तड़प के गोवंश मर जाते हैं। मकर संक्रांति को बेजुबान गोवंश को एक बार खिलाने वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मकर संक्रांति पर पुण्य कमाने के लिए जितना पैसा खर्च करना चाहते हो उतना पैसा एक साथ खर्च न करके मकर संक्रांति से पहले से लेकर मकर

नगर निगम जयपुर सतर्कता शाखा की टीम द्वारा की गई कार्रवाई, 4 केन्द्र सामान जब्त

-3 हजार रुपये का किया कैरिंग चार्ज वसूला-
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम जयपुर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार एवं पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में शुक्रवार को सतर्कता शाखा की द्वारा नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में रामबाग सर्किल से एयरपोर्ट तक, बी-2 बाईपास से एसएफएस चैराहा, मानसरोवर न्यू सांगानेर रोड एवं 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 3 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 4 केन्द्र सामान जब्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता ने बताया कि नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में रामबाग सर्किल से एयरपोर्ट तक, बी-2 बाईपास से एसएफएस चैराहा, मानसरोवर न्यू सांगानेर रोड एवं 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से भोजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मीठ पर 3 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइष करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

जयपुर पूर्व में वाहन चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, दो शक्तिर गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिलें बरामद

जयपुर। जयपुर शहर पूर्व में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम कसते हुए जिला विशेष टीम जयपुर पूर्व और पुलिस थाना जामडोली की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त कार्रवाई में संगठित वाहन चोर गिरोह के दो शक्तिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आरोपियों ने पूछताछ में दो दर्जन से अधिक वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन (IPS) ने बताया कि शहर में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल (RPS) के सुपरविजन और सहायक पुलिस आयुक्त आदर्श नगर सुश्री लक्ष्मी सुधार (RPS) के मार्गदर्शन में जिला विशेष टीम और पुलिस थाना जामडोली की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने आसूचना संकलन के बाद कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों—वीरेंद्र उर्फ विक्रम मीणा (23) निवासी हड़िया, थाना महुआ जिला दौसा



हाल निवासी श्याम नगर कॉलोनी, पुराना बगराना, थाना कानोता जयपुर पूर्व और शैलेन्द्र कुमार जाटव (20) निवासी टिकरी जाफरान, थाना महुआ जिला दौसा हाल किरायेदार वेदनगर कॉलोनी, हाथी गांव, थाना आमेर जयपुर—को गिरफ्तार किया। दोनों को पुलिस थाना जामडोली के प्रकरण संख्या 20/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से थाना जामडोली, कानोता, खोह नागौरियान, जयसिंहपुरा खोर और खेड़ली मोड़ (भरतपुर) क्षेत्र से चोरी की गई कुल 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

इनमें 7 हरो स्लेंडर और 1 यामाहा आर-15 बाइक शामिल है, जबकि एक स्लेंडर बिना चेंसिस, इंजन और रफिस्टेशन के भी जब्त की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर जयपुर शहर में रात के समय और मौका मिलने पर दिन में भी वाहन चोरी करते थे। एक बार में तीन से चार बाइक चोरी कर उन्हें गांव ले जाकर 7 से 8 हजार रुपये में बेच देते थे। कई बार ग्राहकों की मांग पहले से तय रहती थी और उसी के अनुसार बाइक चोरी की जाती थी। अब तक जयपुर शहर से करीब दो दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी करीब आरोपियों ने स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वीरेंद्र उर्फ विक्रम मीणा थाना महुआ, जिला दौसा का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं, जबकि शैलेन्द्र जाटव पर भी आधा दर्जन अपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। जिला विशेष टीम की वाहन चोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।

जयपुर में 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 में निजी खातेदारी करीब 03 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस, राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सिवाव, सेक्टर रोड के पास, जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाये भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल, पत्थरगद्दी व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भिक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जापते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के पक्ष को सही माना, रिजर्व लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपीलों पर गुरूवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल रिजर्व या वेटिंग लिस्ट में नाम होने मात्र से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ एवं खंडपीठ के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें आयोग को नियमों में अंकित अवधि के व्यतीत हो जाने के बावजूद रिजर्व लिस्ट से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे।

क्या था मामला?
आयोग के संयुक्त विधि परामर्शी राकेश ओझा ने बताया कि यह प्रकरण कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2013 एवं 2019 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती- 2020 से संबंधित था। इसमें मुख्य सूची के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रहे पदों पर अराक्षित सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। इस पर वेटिंग लिस्ट में शामिल



यति जैन, आकृति सक्सेना और विवेक कुमार मीणा जैसे उम्मीदवारों की याचिका पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसे आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर चुनौती दी थी, परंतु खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को पथावत रखते हुए आयोग की अपील को खारिज कर दिया था। अंततः आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु
नियमों की सर्वोच्चता: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अराक्षित सूची की वैधता मुख्य सूची भेजे जाने की तिथि से केवल 6 माह

के लिए होती है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद सूची निष्प्रभावी हो जाती है। कानूनी अधिकार का अभाव: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने व्यवस्था दी कि केवल अराक्षित सूची में नाम होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अपरिहार्य कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता। आयोग की स्वायत्तता: न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्र सवैधानिक निकाय है। राज्य सरकार द्वारा अपील न करने की स्थिति में भी आयोग को भर्ती नियमों की रक्षा हेतु अपील करने का पूर्ण अधिकार है। भर्ती प्रक्रिया की शुचितता: निर्णय में उल्लेख किया गया कि यदि चयन प्रक्रिया अनिश्चित काल तक खुला रखा जाता है, तो यह आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नए पात्र अभ्यर्थियों के अवसरों का हनन होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द करते हुए अपने निर्णय में यह कहा कि हालांकि अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति हो सकती है, किंतु स्थापित नियमों और समय सीमा के विरुद्ध जाकर नियुक्तियों का आदेश नहीं दिया जा सकता।

हवामहल-आमेर जोन में बकाया कर वसूली पर सरस्वी, 18.58 लाख रुपए की कार्रवाई

-चार संपत्तियों पर कार्रवाई, 03 ने मौके पर जमा कराए कर, 01 संपत्ति सीज

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम जयपुर द्वारा बकाया नगरीय विकास कर वसूली को लेकर सख्ती जारी है। नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार शुक्रवार को हवामहल-आमेर जोन क्षेत्र में बकाया नगरीय विकास कर नहीं चुकाने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हवामहल-आमेर जोन उपायुक्त के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा नगर निगम जयपुर मुख्यालय की सतर्कता शाखा के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान कुल चार संपत्तियों को चिन्हित किया गया, जिन पर नगरीय विकास कर के रूप में कुल रूपये 18,58,997 थे- की बकाया राशि थी। जोन उपायुक्त सीमा चैधरी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान तीन संपत्ति धारकों ने मौके पर ही बकाया कर राशि जमा करा दी, जिसके पश्चात उनकी संपत्तियों को कुर्की से मुक्त कर दिया गया। वहीं एक संपत्ति पर बकाया राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार सीज (सील) की कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया



कि बकाया कर जमा नहीं कराने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ

आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम का उद्देश्य कर वसूली सुनिश्चित कर शहर में बेहतर नागरिक सुविधाएं और विकास कार्यों को गति देना है। नगर निगम जयपुर ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे समय पर अपना बकाया कर जमा कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कुर्की एवं सीज जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यक नम्बर		रॉयल पत्रिका
विजली फॉन्ट के लिए		
टोल फ्री नंबर	18001806507	जलदाय कार्यालय
वाट्सएप नंबर	9414037085	फायर ट्रिगेड
कन्टर केयर	22030000	
आईबीआरएस	1912	
कचरा गाड़ी के लिए		
ग्रेटर	2747400	एएसएमएस इमरजेंसी
सीवेरेज लीकेज	2607500	महिला चिकित्सालय
हेरिटेज	2607500	जनना हॉस्पिटल
टोल फ्री नंबर	14420	SDMS
		SDMS ब्लड बैंक
		कल्याण ब्लड बैंक
पुलिस की मदद के लिए		
साइबर क्राइम	1930/2360094	नगर निगम
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38	बर्ड बाइक
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	जैन इन सफरिंग
वाइल्ड हेल्पलाइन	1098	हेल्थ ड्रैट
महिला हेल्पलाइन	1098	पशु चिकित्सालय
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	
		2706624
		2747400
		102/108
		2518333
		22610616
		22378721
		22574189
		22518222
		22721771
		2747400
		9867345580
		8107299711
		7300558000
		2747400

सैहत पर गंभीर असर डाल सकती हैं सर्द हवाएं जानें कैसे बचें - डॉ. सुमीत गर्ग

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। सर्दियों के मौसम में सुबह उठना, ठंडी हवाओं का सामना करना और रोज़मर्रा के काम के लिए घर से बाहर निकलना कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। उत्तर भारत में कोहरा और सर्द हवाएं न केवल जनजीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती हैं। ठंड का असर केवल दिनचर्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दिल, फेफड़ों और संपूर्ण शरीर पर सीधा प्रभाव डालता है। सरकारी आंकड़े इस खतरा की गंभीरता को साफ़ दिखाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच शीत लहरों की चपेट में आने से देश में 3,600 से अधिक लोगों की मौत हुई। भारत की लगभग 90 करोड़ आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है, जिन्हें कोर कोल्ड वेव जोन माना गया है। **दिल पर पड़ता है सीधा असर :-**

ठंडी हवाओं का सबसे गहरा असर हृदय पर पड़ता है। ठंड कोर्टिसोल जैसे स्टेस हार्मोन बढ़ाता है, जिससे रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अत्यधिक ठंड या अचानक आई ठंडी लहर के 2 से 6 दिन बाद हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा सबसे अधिक रहता है। ठंड में शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे स्टेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज़ होती है और खून के थक्के बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। **सांस संबंधी दिक्कतें भी बढ़ती हैं :-** ठंडी और शुष्क हवा सांस की नलियों को इरिटेट करती है। इससे खांसी, ब्रॉन्काइटिस, अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। सर्दियों में लोग



सर्द हवाओं से सबसे अधिक खतरा हृदय रोगियों, पहले हार्ट अटैक झेल चुके मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्थमा-सीओपीडी और डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को होता है। डायबिटीज़ के मरीजों में सर्दियों में शूगर असंतुलित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। **सर्दियों में होने वाली आम गलतियां :-** अक्सर लोग सुबह उठते ही बिना वार्म-अप ठंड में बाहर निकल जाते हैं या अचानक भारी काम शुरू कर देते हैं। यह स्थिति दिल और दिमाग पर अतिरिक्त दबाव डालती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह दवाइयों में बदलाव करना भी एक बड़ी गलती है। **ठंडी हवाओं से बचाव कैसे करें :-** सर्दियों में एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय कई परतों में कपड़े

पहनना अधिक सुरक्षित होता है। इनर, शर्ट, स्वेटर और जैकेट की परतें शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं। टोपी, मफलर, दस्ताने और मोज़ों का प्रयोग ज़रूरी है, ताकि कान, हाथ-पैर सुरक्षित रहें। सुबह-शाम बहुत ठंड या स्मॉग के समय बाहर निकलने से बचें। यदि निकलना ज़रूरी हो तो मास्क पहनें। घर गर्म रखने के लिए अंगीठी का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो जानलेवा हो सकती है। हीटर का सीमित उपयोग करें और कमरे में वेंटिलेशन बनाए रखें। सर्द हवाओं से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इनके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मौसम के अनुसार जीवनशैली में बदलाव, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और समय पर चिकित्सकीय सलाह सर्दियों में स्वस्थ रहने की कुंजी है।

दहेज प्रथा को रोकने के लिए की अनूठी पहल

-तीनों फैमिली ने बिना किसी लेन देन के साथ शादी कर अनूठी व अनुकरणीय मिसाल पेश की

मोहम्मद अली पठान (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर अनुना मोहल्ला निवासी सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले खानजादा परिवार में एवम् न्याय विभाग चूरू में कार्यरत शमशेर खान इस्माईलखानी की पुत्री समून खान की शादी बिसाऊ निवासी रेल्वे से सेवानिवृत्त सीटीआई शफी खां के पुत्र मोहम्मद शाहिल के साथ तथा शमशेर खान इस्माईलखानी के पुत्र एस गालिब की शादी चूरू निवासी आरएससी से सेवानिवृत्त लियाकत खां की पुत्री मुस्कान खान के साथ सादगी के साथ सम्पन्न हुई। शादी में दहेज का लेन देन ना कर सादगी के साथ शादी सम्पन्न कर अनूठी मिसाल पेश की है तथा खानजादा परिवार में हुई इस शादी के माध्यम से समाज



के लिए एक अनूठा उदाहरण एवं अनुडी व अनुकरणीय मिशाल पेश की है। इस पहल का समाज के लोगों के द्वारा भी सराहना की जा रही है। दोनों परिवारों ने मिलकर इस दहेज लेना देन के कार्य एवं रीति को वर्जित करते हुए समाज को एक नई दिशा दी। समाज के लोगों ने कहा कि समाज में अनेकों कुरीतियों को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा

कि दोनों पक्षों के इस प्रयास से समाज में जागृति आएगी, उन्होंने सभी से इस सकारात्मक सोच को अपनाने का आह्वान किया। समाज के लोगों ने भी कहा कि सामाजिक कुरीतियों के कारण हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे समाज व रिश्तेदारों को भी दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे।

रतननगर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह

रतननगर (रॉयल पत्रिका)। श्री बृजलाल बुधिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतननगर में हुआ दो प्रतिभावांन बेटियों का सम्मान समारोह स्थानीय श्री बृजलाल बुधिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर की दोनों होनहार बेटियों निकिता मीणा (आरजेएस) तथा डॉ. पूजा मीणा (कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर) का उनकी अभूतपूर्व सफलता पर स्वागत और सम्मान किया गया। हाल ही घोषित परिणामों में निकिता का राजस्थान न्यायिक सेवा में व पूजा का कॉलेज प्राध्यापक पद पर चयन हुआ है। विद्यालय परिवार द्वारा दोनों प्रतिभावांन



बेटियों व उनके माता-पिता का माला पहनाकर व साफा बांधकर अभिनन्दन किया गया। सम्मान से अभिभूत निकिता और पूजा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के आशीर्वाद और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने विद्यालय की छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि

एकाग्रता और निरन्तर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल प्रजापत ने इस अवसर पर इन बेटियों से प्रेरणा लेने के लिए कहा, इस अवसर पर समस्त शैक्षिक स्टाफ व छात्राएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन प्रेम प्रकाश व्याख्या ने किया।

जरूरतमंद परिवारों को

ऊनी कम्बल बांटे



सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। सहसास सोशल वेलफेयर सोसायटी सवाई माधोपुर के सदस्यों द्वारा पिछले दिनों से लगातार गर्म कम्बल व जर्सी बांटी जा रही है। इसी क्रम में संस्था के सदस्यों द्वारा बंबोरी क्षेत्र में आर्थिक

रूप कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को 25 ऊनी कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रवीण जैन, अनिल कुमार सक्सेना, जावेद अनवर, पीयूष सिंघल, अल्ताफ नूर, नीलेश जैन, शोएब तनवीर आदि उपस्थित रहे।

3 साल से फरार आरोपी सुरेंद्रपाल सिंह उर्फ

भोला गिरफ्तार, सीजेएम कोर्ट में पेश

विनोद सोखल (रॉयल पत्रिका)। श्रीकरणपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 3 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्थायी गिरफ्तारी वारंटी की तामील करते हुए सुरेंद्रपाल सिंह उर्फ भोला पुत्र बलवंदर सिंह, जाति खत्री सिख, निवासी खालसा नगर, पंजाबी सिटी श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर



था और लगातार फरारी काट रहा था। आखिरकार करणपुर पुलिस की सतर्कता और लगातार प्रयासों के चलते आरोपी को दबोच लिया

गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीजेएम न्यायालय, श्रीकरणपुर में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी पर ₹5000 का जुर्माना लगाते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में करणपुर थाना के कांस्टेबल कन्हैया लाल मीणा की विशेष भूमिका रही, जिनकी मेहनत और सतर्कता से आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर आमजन में भरोसा बढ़ा है।

राजकीय उपजिला अस्पताल के लिए नगर

पालिका ने भूमि आवंटन के आदेश जारी किये

-कलेक्टर ने नगरपालिका को भूमि हस्तांतरित कर

कारवाई आवंटन की प्रक्रिया पूरी की

लाडनू (रॉयल पत्रिका)। जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र सिंह खड़गावत के निर्देशन में नये जिले डीडवाना कुचामन के विस्तार के साथ-साथ जिले में आवश्यक सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर के निर्देश पर लाडनू में राजकीय उपजिला चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन के आदेश जारी किये हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मो. मुस्ताक खान कायमखानी ने बताया कि इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावल्या ने कहा कि जिले में आमजन से जुड़ी सुविधाओं के विकास को गति देने के लिए जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत के निर्देश पर लाडनू में राजकीय उपजिला चिकित्सालय के लिए आवंटित की गई है जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित दुरदराज के मरीजों को और अधिक सुविधाजनक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कायमखानी ने बताया कि कई वर्षों के बाद अब लाडनू में राजकीय उपजिला चिकित्सालय का बनेगा नया भवन बनेगा, इसके संबंध में जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन के आदेश के बाद नगर पालिका मंडल लाडनू ने चिकित्सालय के नये भवन हेतु भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का आदेश जारी किया है। पास में पार्क, पार्किंग और सड़कें भी निर्मित की जाएगी, मौजूदा अस्पताल के सामने नगर पालिका की खाली जमीन पर बनेगा अस्पताल का नया सबसे बड़ा भवन।

बीड़बायला में कृषि भूमि पर घड़ल्ले से अवैध

कॉलोनियां, प्रशासन की मिलीभगत के आरोप

विनोद सोखल (रॉयल पत्रिका)। श्रीगंगानगर बीड़बायला (रॉयल पत्रिका)। बीड़बायला कस्बे में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों का खेल खुलेआम चल रहा है। नियमों को ताक पर रखकर खेतों को छोटे-छोटे भूखंडों में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब प्रशासनिक मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। सूत्रों के अनुसार, कृषि भूमि का गैरकानूनी रूप से प्लॉटिंग कर सस्ते दामों पर भूखंड बेचे जा रहे हैं। न तो भूमि रूपांतरण (कन्वर्जन) की अनुमति ली गई है और न ही नगर नियोजन के नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके बावजूद न बिजली कनेक्शन रोकने की कार्रवाई हो रही है और न ही निर्माण पर कोई प्रभावी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध कॉलोनियाइजर भोले-भाले लोगों को

फर्जी दस्तावेज दिखाकर प्लॉट बेच रहे हैं। बाद में इन कॉलोनियों में सड़क, पानी, नाली और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग केवल नोटिस तक सीमित रह जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कृषि भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग हो रही है, तो राजस्व, नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रभावशाली लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है? अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में यह अवैध कॉलोनियां बड़े विवाद और जनसमस्याओं का कारण बन सकती हैं। अब देखा यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब तक चुप्पी साधे रहता है, या फिर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।

13 वर्षीय बालिका पर एक युवक ने तेजाब फेंका

विनोद सोखल (रॉयल पत्रिका)। केसरीसिंहपुर कस्बे में शुक्रवार सुबह सनसनीखेज घटना सामने आई। स्कूल जा रही 13 वर्षीय बालिका पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 10 निवासी बालिका सुबह करीब 10 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जा रही थी। इसी दौरान स्कूल के पास ही एक युवक ने अचानक उस पर तेजाब फेंक दिया। बालिका कक्षा 9 की छात्रा है और एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। गनीमत रही कि तेजाब बालिका के पहने हुए कोट और कपड़ों पर ही गिरा, जिससे बड़ा हादसा टाल गया। **मां को बताई आपबीती:-** अचानक हुई घटना से बालिका घबरा गई



और तुरंत पास ही काम कर रही मां के पास पहुंची और पूरी आपबीती बताई। परिजन तुरंत जेठ राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया। **मामले की जांच में जुटी पुलिस:-** सूचना मिलने पर थानाधिकारी बलवंत राम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक आरोपी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। वारदात के बाद मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और पीड़ित परिवार से जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

हजरत मीरुशाह

रहमतुल्ला अलैह का

108 वां उर्स मुबारक



चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर ईदगाह मोहल्ले में दरगाह हजरत मिरू शाह रहमतुल्ला अलैह का 108 वां उर्स बड़ी हकीकत के साथ मनाया जा रहा है दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत गुलामनबी खान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी चूरू के मशहूर-मौरूफ बुजुर्ग कुतबे वक्त हज़रत किब्ला मीरूशाह रहमतुल्ला अलैह का 108 वां उर्स मुबारक 17 जनवरी 2026 शनिवार मुनअक़िद हो रहा है। हज़रत यह कोई दूकी-छुपी बात नहीं है, बुजुर्गनि दीन के फय्यूज़ों बरकात जिस तरह उनकी हयाते-पाक में जारी व सारी रहते हैं, इसी तरह विसाल के बाद भी उनकी मदद और फरयादरसी का सिलसिला चलता रहता है। लिहाजा आप हज़रत से गुज़ारिश है तेष शुदा प्रोग्राम के मुताबिक उर्स मुबारक में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शारीक होकर फय्यूज़ों बरकात हासिल करें। दिन में फूल मालाएं और चादर पोसी होगी एवं प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा शनिवार मारूफ नमाज़े फजर कुरआन खानी - नातखानी शनिवार सुबह 8.00 बजे तकरीर ओलमा-ए-किराम सुबह 11.00 बजे फातिहा एवं जुलपोशी के बाद तकसीम लंगर और बाद नमाज़ जोहर के सलातो सलाम के साथ ही कुल की रसम अदा की जाएगी।

SAR प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप,

मुस्लिम समाज ने सौंपे जापन



इकबाल शाह, बनेड़ा (रॉयल पत्रिका)। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (SAR) प्रक्रिया को लेकर बनेड़ा क्षेत्र में असंतोष सामने आया है। शुक्रवार को आम मुस्लिम समाज द्वारा सदर बनेड़ा की ओर से निर्वाचन विभाग एवं उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। कांग्रेस अल्पसंख्यक ग्रामीण जिला अध्यक्ष इकबाल मोहम्मद शाह ने बताया कि बनेड़ा तहसील के मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनके नाम काटे जा रहे हैं उन्होंने मांग की है कि ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर गलत तरीके से हटाए गए नाम को तुरंत मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आम मुस्लिम समाज सदर इमरान अंसारी द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान SAR प्रक्रिया के दौरान प्रारूप-7 का दुरुपयोग कर बिना किसी आवेदन, सूचना अथवा ठोस कारण के बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि मतदाताओं को न तो कोई नोटिस दिया जा रहा है और न ही उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, जो निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि BLO स्तर पर बिना समुचित जांच के नाम काटे जा रहे हैं, जिससे योग्य मतदाताओं का मताधिकार प्रभावित हो रहा है। संगठन ने मांग की कि ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर गलत तरीके से हटाए गए नामों को पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जाए। ज्ञापन में कहा कि फार्म-6, 7 एवं 8 से संबंधित आवेदनों को निर्वाचन आयोग के नियमों एवं

कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा जापन

मोहम्मद यासीन (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण एस.आई.आर.एव.एव मनरेगा योजना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस मुख्यालय पाली स्थित कांग्रेस भवन पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। तत्पश्चात जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं जिले के समस्त कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों, मण्डल अध्यक्षों ने जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा एवं विधायक भीमराज भाटी, पूर्व विधायक सुशवीरसिंह जोजावर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस भवन में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित कांग्रेस जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, जिले के समस्त मंडल अध्यक्षगण, एवं ब्लॉक प्रभारीगण को सम्बोधित करते हुए पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन में हुई व्यापक त्रुटियों के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व हम सभी कांग्रेसजनों का है जिसे हम सभी मिलकर निभाएंगे। यह कोई जनसभा नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े संगठनात्मक साधियों की गंभीर और उद्देश्यपूर्ण बैठक है। पाली जिले में किसी भी पात्र मतदाताओं के नाम कटाना लोकतंत्र की हत्या है। यह प्रशासनिक भ्रष्ट नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश है, जिसका सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग, महिलाएं और मजदूर वर्ग हैं। कांग्रेस पार्टी हर उस नागरिक के साथ खड़ी है, जिसका नाम, हक और सम्मान छीना जा रहा है। उन्होंने उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा कर मनरेगा व एसआईआर व संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी सरकार और आर.एस.एस. संगठन के लोगों द्वारा सरकारी बी.एल.ओ. पर अनुचित दबाव बनाकर गलत और बाहरी लोगों के नाम जुड़वाए जा रहे हैं तथा कांग्रेसी विचारधारा के लोगों के नाम गलत तथ्यात्मक जानकारी देकर कटवाए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा जापन



यह सब SAR के पश्चात् जारी प्रथम ड्राफ्ट सूची में से मतदाताओं के नाम काटकर आने वाले नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव हेतु बनने वाली मतदातासूची को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है, जो पूर्णतः अनैतिक है। ज्ञापन में प्रत्येक बूथ पर एक-एक आदमी द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियों के फार्म प्रस्तुत करना एवं उपखण्ड निर्वाचन विभाग की मिलीभगत को दर्शाता है। इस दौरान विधायक भीमराज भाटी ने कहा कि जिन पात्र मतदाताओं के विरुद्ध दलगत राजनीति के चलते आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही है, उन मतदाताओं को बिना नोटिस जारी किये ही, उनका पक्ष सुने बिना ही आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जब कि ऐसे मामलों में बीएलओ को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। विधायक भाटी ने कहा कि पाली जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता व कांग्रेस बीएलए - 2 से विशेष रूप से अपने अपने बूथ पर गम्भीरता से ध्यान रखकर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिना किसी ठोस कारण एवं विवरण के बड़ी संख्या में कांग्रेस के पात्र मतदाताओं के नाम फॉर्म-7 के जरिये बड़ी तादाद में आपत्तियां जमा कर नाम काटे जाने का बूथ स्तर पर बीएलओ के समक्ष विरोध करें। इस दौरान पूर्व विधायक सुशवीर सिंह जोजावर कहा कि नियमानुसार इलेक्ट्रोल मेन्सुअल 2023 के पैरा संख्या 11.3.2 (2) के अनुसार ब्लक (थोक) में आवेदन प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फॉर्म (दावा अथवा आपत्ति हेतु) प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मायदा प्राप्त राजनेतिक

दलों के बीएलए 2 प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा करा सकते हैं। फार्म में मतदाता की सम्पूर्ण जानकारी उसका मोबाईल नंबर साक्ष्य अंडरटेकिंग संलग्न होना आवश्यक है। जानकारी प्राप्त हुई है कि बीएलओ पर अनुचित दबाव बनाकर नियमों के विरुद्ध एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बल्क में एक ही दिन में सैकड़ों की संख्या में फॉर्म 7 एवं फार्म 6 प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है तथा इसे आवेदनों पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाए। साथ ही उन्होंने ने ऐसे सभी नियम विरुद्ध जमा फॉर्म 6, 7 एवं 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाए। बल्क में जमा हुए आवेदनों पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाए। साथ ही नियम विरुद्ध आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावे। बैठक में प्रमुख रूप से पाबुसिंह राजावत, शहर ब्लॉक अध्यक्ष हकीम भाई, रोहट ब्लॉक अध्यक्ष पीराराम पटेल, भेरूसिंह राजपुरोहित सोनाणा, प्रवीण कोठारी, राजीव गांधी पंचायती राज जिलाध्यक्ष मदनसिंह जागरवाल, जोगाराम सोलंकी, लक्ष्मीनारायण तंवर, यशपालसिंह शिवतलाव, नेपालसिंह पावा, राकेश चौहान, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोरधन देवासी, एसी प्रकाश जिलाध्यक्ष सुनील बेरवा, नाहर सिंह जाखोड़ा, गुलाब सिंह गिरेवर, मेहबूब भाई टी, भेरूसिंह सोनाणा, यशपालसिंह कुम्पावत, नरेंद्र सिंह गुर्जर, ताराचन्द चन्दनानी, महेश परिहार, पीसाराण बामणिगा, इलियास चढ़वा, दलवीर सिंह चौहान, इंद्रसिंह राजपुरोहित, पहलाद कंडारा, राकेश चौहान, भाखरराम देवासी, अनीस पठान, ताराराम सीरवी, बाबुराम भाटी, गजेन्द्र सिंह चौहान, शकील अहमद नागोरी, रघुनाथ सिंह मंडली, राजू सलौंकी, जयेश सोलंकी,वेणाराम राराबड़ा,पुष्प सोनी, दिनेश देवे, जीवराज चौहान, याकूब मोयला, सुरेश चौहान, जमील खान कुरेशी, पुखराज गर्ग, चन्द्रपाल पुनायात, अनिल सिंह निम्बाडा सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे।



कृति सेनन

से कितने छोटे हैं उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया?

कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। खबरे हैं कि वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं। इसी बीच आइए जानते हैं दोनों की उम्र और नेटवर्थ के बीच कितना फासला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी



पर्सनल

लाइफ को लेकर भी

अक्सर कृति और कबीर को कई बार साथ में स्पॉट किया जा चुका है। हाल ही में कबीर नूपुर की शादी में भी शामिल हुए थे। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर अभी तक चुप्पी बनाए रखी है। बता दें दोनों के बीच 9 साल का एज गैप है। जहां कृति 35 साल की है, वहीं उनके बॉयफ्रेंड कबीर अभी 26 साल के हैं। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कृति सेनन की नेटवर्थ 82 करोड़ है। वो एक फिल्म के लिए 5-8 करोड़ चार्ज करती हैं। वहीं कबीर बहिया फैमिली की नेटवर्थ 4000 करोड़ है। इन सभी के अलावा कबीर का इंडियन क्रिकेटर्स से खास कनेक्शन है।



अचानक आई उदासी को ऐसे करें दूर

ऋतिक रोशन

एक्टर ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर अक्सर खास पोस्ट कर फैंस के साथ रूबरू होते रहते हैं। लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने बताया कि अचानक आई उदासी को दूर कैसे करें। बउहोने इससे निपटने का आसान उपाय भी बताया। ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर एक डीप और थॉट प्रोवोकिंग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सुबह की अचानक आई उदासी और इमोशन के बारे में खुलकर बात की है। पोस्ट की शुरुआत उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अच्छे समय बीतने के बाद अचानक दुनिया की सारी खुशियां सामने आ जाती हैं। लेकिन फिर भी इस बेतुकी, बेमतलब उदासी से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। यह उदासी बिना चेतानवी के हमें अपनी जद में ले लेती है। ऋतिक ने कहा कि वह अपनी मौजूदा इमोशन को शब्दों में उड़ेल रहे हैं। फिर उन्होंने साइंस का जिक्र किया, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. जिल बोलेट टेलर के अनुसार, कोई भी भावना अपने शुद्ध रूप में सिर्फ 90 सेकंड तक रहती है। उसके बाद वह बदल जाती है या किसी दूसरी भावना में मिल जाती है, तो ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लिखा, 'इसमें मुझे 45 सेकंड लगे, 45 बाकी हैं' पोस्ट के लास्ट में उन्होंने उन लोगों को मेसन किया जो सच्ची अजीब पोस्ट को समझ नहीं पाएंगे या बाद में नागज होगे। उन्होंने कहा, 'मेरे दोस्तों, आप सच में जिंदगी कैसे जी रहे हैं जैसे इसे जीना चाहिए।' बता दें, ऋतिक रोशन अक्सर अपनी पर्सनल जर्नी, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करते हैं।

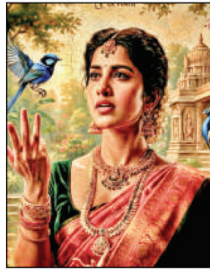
नूपुर सेनन की शादी में दिशा पटानी ने बटोरीं सुखियाँ

एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के जश्न की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। जहाँ दूल्हा-दुल्हन अपनी नई शुरुआत के लिए बधाई पा रहे हैं, वहीं इस शादी के एक वीडियो ने बॉलीवुड गलियारों में नई चर्चा खेड़ दी है। एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के जश्न की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। जहाँ दूल्हा-दुल्हन अपनी नई शुरुआत के लिए बधाई पा रहे हैं, वहीं इस शादी के एक वीडियो ने बॉलीवुड गलियारों में नई चर्चा खेड़ दी है। यह चर्चा किसी और की नहीं बल्कि एक्ट्रेस दिशा पटानी और उनके साथ नजर आए एक 'मिस्ट्री मैम' की है। दिशा पटानी और एक आदमी, जिसे कई लोग ऑनलाइन पंजाबी सिंगर तलविंदर मान रहे हैं, से जुड़ा एक छोटा सा पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इवेंट के क्लिप में दोनों को एक-दूसरे के करीब खड़े, हाथ पकड़े हुए और बाद में एयरपोर्ट से एक साथ निकलते हुए दिखाया गया। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब दिशा पटानी की करीबी दोस्त मौनी रॉय ने सार्वजनिक रूप से तलविंदर के लेटेस्ट एल्बम की तारीफ की। हालांकि यह तारीफ पूरी तरह से प्रोफेशनल लग रही थी, लेकिन इसका समय, खासकर बड़ती खेटिंग की अफवाहों के बीच, सिंगर को एक बार फिर सुखियों में ले आया। और कई लोग वही सवाल पूछ रहे हैं: आखिर तलविंदर कौन हैं, और वह अचानक हर जगह क्यों दिख रहा है? मौनी रॉय, जो दिशा पटानी की बेस्ट फ्रेंड हैं, ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तलविंदर के जल्द ही रिलीज होने वाले एल्बम को प्रमोट किया और लिखा, 'इंतजार नहीं कर सकती भाई! यह बहुत पसंद आया। नूपुर और स्टेबिन की शादी का एक छोटा वीडियो बड़े पैमाने पर सर्कुलेंट हुआ है, जिसमें दिशा पटानी मुस्कुराती हुईं और मेहमानों से बातचीत करती दिख रही हैं। वह एक छोटा सा पल था जब वह अपने बगल में खड़े एक आदमी का हाथ पकड़े हुए दिखीं। सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत सोशल मीडिया पर उस 'रहस्यमयी आदमी' की पहचान तलविंदर के रूप में की, जो एक पंजाबी सिंगर है और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने और सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाने के लिए जाना जाता है।



नागबंधन में पार्वती बनीं नभा नतेश, पोस्टर में खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक ने खींचा ध्यान

कल मेकर्स ने आने वाली फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी, जिसमें बस एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी। इस पोस्टर ने सबको पार्वती की पहचान को लेकर सोच में डाल दिया था, साथ ही आज रिलीज करने का वादा भी किया गया था। अब आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और पार्वती से पर्दा उठ चुका है। अपकमिंग फिल्म नागबंधन में पार्वती के किरदार में नभा नतेश को पेश किया गया है, और इसके साथ मेकर्स ने उनका बेहद खूबसूरत पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। सोशल मीडिया पर मेकर्स ने पार्वती के रोल में नभा नतेश को रिलीज किया। खूबसूरत एक्ट्रेस ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी में बेहद स्टनिंग और अट्रैक्टिव लग रही हैं, जो पूरी तरह से एलिगेंस और ग्रेस दिखा रही हैं। पार्वती को रिलीज करने के साथ-साथ मेकर्स ने फिल्म का टाइटल, नागबंधन भी रिलीज किया और कैप्शन लिखा- 'रहस्यों से भरी दुनिया में, उसका विश्वास ही उसकी किस्मत बन जाता है 'नागबंधन के पोस्टर में पार्वती के रूप में प्रेसफुल नजर आ रही नभा नतेश सिर्फ किरदार ही नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म का वादा भी करती हैं जो भारतीय संस्कृति में गहराई से रची-बसी है। पार्वती की गंगली पर बैठ खूबसूरत पक्षी एक सरप्राइज एलिमेंट जोड़ता है, वहीं बैकग्राउंड में मोर और मंदिर का माहौल इस बात का भरोसा दिलाता है कि कहानी भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े एक अलग ही आयाम को छुएगी। जहां नभा नतेश इस फिल्म में बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाली हैं, वहीं वह तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन 2019 में आई द्रुमाई संकर से उन्हें बड़ी पहचान मिली, जिसके बाद वह 'द्रुमाई ब्यूटी' के नाम से लोकप्रिय हो गईं। इसके अलावा, टाइटल के साथ जुड़ा दिलचस्प टैगलाइन 'द सीक्रेट ट्रेजर' फिल्म में छुपे रहस्य की ओर इशारा करता है, जिसे कहानी के साथ धीरे-धीरे खोला जाएगा। इस खुलासे ने आने वाले कंटेंट को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। नागबंधन की कहानी, स्क्रीनप्ले और निर्देशन अभिषेक नामा ने संभाला है। फिल्म को किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसे समर 2026 में पैन-इंडिया रिलीज करने की योजना है।



किसी को बुरा दिखाकर अच्छा नहीं बन सकते', पेड नेगेटिव पीआर पर मड़की

सोनल चौहान

बॉलीवुड में पेड नेगेटिव पीआर और सोशल मीडिया ट्रोलिंग अब एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कई एक्टर्स इस तरह की जानबूझकर फैलाई जा रही नकारात्मकता से परेशान हैं। इसी बीच अभिनेत्री सोनल चौहान ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और कहा कि किसी को नीचा दिखाकर कोई खुद ऊपर नहीं उठ सकता। सोनल का मानना है कि बॉलीवुड में कॉमिंटेशन तो होनी चाहिए, लेकिन वह सकारात्मक और रचनात्मक हो। ट्रोलिंग और पेड नेगेटिविटी से न सिर्फ एक्टर्स की मानसिक शांति प्रभावित होती है, बल्कि उनके काम और मेहनत पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट के जरिए अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, 'एक्टर्स के खिलाफ चल रही ये पेड पीआर अब बंद होनी चाहिए। इतनी नेगेटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। किसी को बुरा दिखाकर कोई अच्छा नहीं बन सकता। हम एक-दूसरे के लिए खुश क्यों नहीं हो सकते? सब बहुत मेहनत करते हैं, अगर हम सपोर्ट करें, तो इंडस्ट्री का माहौल बहुत बेहतर हो सकता है। हमें बस थोड़ा सकारात्मक रहना है।' सोनल से पहले कई एक्टर्स पेड नेगेटिव पीआर के खिलाफ आवाज उठाते दिखे। तारा सुतोारिया ने हाल ही में बताया कि उनके खिलाफ पेड नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झूठी अफवाहों और ट्रोलिंग से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वे चाहती हैं कि लोग उनके काम पर फोकस करें, न कि बनाई हुई कहानियों पर। यामी गौतम ने भी पेड हाइप और नेगेटिव कैपेन को इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह एक तरह की वसूली है, जो धीरे-धीरे दीमक की तरह पूरी इंडस्ट्री को खा जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री से इस कल्चर को खत्म करने की अपील की।



न्यायालय का सेंसर बोर्ड की मंजूरी से संबंधी जन नायकन के निर्माता की याचिका पर सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश को चुनौती देने वाली, विजय अभिनीत तमिल फिल्म जन नायकन के निर्माता द्वारा दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी देने के एकल-न्यायाधीश के निर्देश पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय में मामले के निपटारे की गति पर सवाल उठाते हुए फिल्म निर्माताओं को राहत के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ से संपर्क करने को कहा। शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय को 20 जनवरी को याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था क्योंकि निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि फिल्म के मामले में अगर देरी होती है तो इससे गंभीर क्षति होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने नौ जनवरी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को जन नायकन को तत्काल सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है। विजय की पार्टी ने अपने राजनीतिक संकेतों के कारण ध्यान आकर्षित किया है। केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने पिछले शुक्रवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की। विजय ने हाल में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलनाा वेत्रो कषगम (टीवीके) की शुरुआत की है। जन नायकन को व्यापक रूप से विजय की राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश करने से पहले उनकी आखिरी फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। फिल्म नौ जनवरी को पोंगल के अवसर पर रिलीज होने वाली थी।हालांकि, सीबीएफसी द्वारा समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के बाद फिल्म को अंतिम समय में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।

शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया



फिल्ममेकर साजिद खान को हाल ही में व्हीलचेयर पर देखा गया। इसके बाद से फैंस उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल, कुछ समय पहले साजिद खान का एक्सरीडेंट हुआ था। इस एक्सरीडेंट में उनके पैरों में चोट आई थी। इसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी। साजिद खान अब पहले से ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। वो शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर पहुंचे। वहां उन्होंने मौजूद पैराजी से बातचीत की। पैराजी ने जब उनसे पूछा कि आप कैसे हैं तो उन्होंने मस्ती में कहा, 'दिख रहा है तेरे को कैसा हूँ। एक्सरीडेंट हो गया था। एक टांग में सर्जरी हुई है, एक टांग फ्रैक्चर हो गई है।' इस के बाद पैराजी उनकी जल्द रिकवरी के लिए विश करते हैं। इसके बाद साजिद कहते हैं कि वो काम पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसीलिए व्हीलचेयर पर ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून केस सेट पर आ गया।बता दें कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अक्षय कुमार होस्ट कर रहे हैं। शो का 27 जनवरी को ग्रैंड प्रीमियर होना है। ये शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर आएगा। इसी के साथ सोनी लिव पर भी शो की स्ट्रीमिंग होगी।

(साभार एजेंसी)

कनाडा ने टी-20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का किया ऐलान

पंजाब टीम में न चुने जाने के कारण भारत छोड़ने वाला खिलाड़ी बना कप्तान

नई दिल्ली, एजेंसी। कनाडा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। कभी क्रिकेट के लिए अपना देश छोड़ने वाले 22 साल के दिलप्रीत सिंह बाजवा कनाडा टीम की कप्तानी करेंगे। पंजाब में जन्में बाजवा साल 2020 में राज्य टीम में चयन न होने के कारण कनाडा चले गए थे।

गुप डी में कनाडा की टीम

पूर्व कप्तान साद बिन जफर, कलीम सना, डिलन डेविलिंग, निकोलस किर्टन और नवनीत धालीवाल भी टीम का हिस्सा हैं। टूर्नामेंट में कनाडा की टीम गुप डी में है, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और यूएई भी हैं। वे 9 फरवरी को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। उनके सभी गुप मैच भारत में होंगे।

दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी कनाडा की टीम

कनाडा की टीम दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। इससे पहले 2024 में खेले गए पिछले एडिशन में भी कनाडा ने न्यूनीत पेशा की थी, जहां उन्होंने आयरलैंड को हराया था। कनाडा ने अमेरिका रीजनल फाइनल जीतकर इस एडिशन के लिए क्वालिफाई किया था। वे पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे, उन्होंने अपने सभी छह मैच जीते।

कौन हैं दिलप्रीत सिंह बाजवा

26 जनवरी 2003 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्में दिलप्रीत के पिता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, जबकि मां हरलीन कौर सरकारी टीचर थीं। साल 2020 में राज्य टीम में चुने न जाने के कारण वह कनाडा चले गए। 2023 वह मॉन्ट्रियल टाइगर्स के लिए ग्लोबल टी20 कनाडा खेले।



अंडर 19 वर्ल्ड कप हेनिल पटेल का 'पंजा', भारतीय शेरों के सामने यूएसए 107 रन पर ढेर

बुलावायो, एजेंसी। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में महज 107 रन पर समेट दिया है। भारत की ओर से हेनिल पटेल ने सर्वाधिक 5 विकेट अपने नाम किए। भारत ने टॉस जीतकर यूएसए को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। यूएसए को 1.3 ओवर में अमरिंदर गिल (1) के रूप में पहला झटका लगा। टीम इस वक्त तक सिर्फ खाता ही खोल सकी थी। यहां से अर्जुन महेश ने साहिल गर्ग के साथ 45 गेंदों में 28 रन जोड़कर यूएसए को संभालने की कोशिश की, लेकिन 29 के स्कोर पर साहिल का विकेट गंवाने के बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया।

साहिल 28 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि अर्जुन ने 29 गेंदों में 2 चौकों के साथ इतने ही रन बनाए। टीम ने 39 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से नीतीश सुदिनी ने अद्वितीय शिकार के साथ पांचवें विकेट के लिए 30 रन की साझेदारी करते हुए टीम को फिर से संभालने की कोशिश की। अद्वितीय 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि नीतीश ने 52 गेंदों में 4 चौकों के साथ 36 रन बनाए, लेकिन टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा नहीं सके। भारत की तरफ से हेनिल पटेल ने 7 ओवरों में महज 16 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि दीपेश देवेंद्रन, आरएस अंबरीश, खिलन पटेल और वैभव सूर्यवंशी ने 1-1 विकेट हासिल किया। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिजान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन और खिलन पटेल के साथ उतरी है। दूसरी ओर, उत्कर्ष श्रीवास्तव की कप्तानी में यूएसए की टीम में साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), ऋत्विक् अर्षीदी, अदनीत झांब, अमोघ आरेपल्ली, नीतीश सुदिनी, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा और ऋषभ शिम्पी शामिल हैं।

दिल्ली प्रदूषण से उठे दुनिया के तीसरे नंबर के दिग्गज खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन

● इंडिया ओपन से वापस लिया नाम



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की जहरीली हवा का असर अब अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भी पड़ने लगा है। दुनिया के तीसरे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए इंडिया ओपन 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है। खास बात यह है कि एंटोनसन ने लगातार तीसरे साल प्रदूषण के कारण दिल्ली में खेलने से इनकार किया है। हालांकि इस फैसले की वजह से विश्व बैडमिंटन महासंघ ने उन पर 5,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 4.15 लाख रुपये) का जुर्माना ठोक दिया है। इलीट टूर्नामेंट के लायक नहीं है दिल्ली - 28 वर्षीय डेनमार्क के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली की स्थिति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, दिल्ली की हवा की स्थिति इतनी खराब है कि यह शहर किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गर्मियों में स्थिति बेहतर होगी, जब दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इंडिया ओपन को लगा बड़ा झटका - एंटोनसन का टूर्नामेंट से हटना आयोजकों के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इंडिया ओपन मंगलवार से इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर अक्सर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है जिससे खिलाड़ियों को सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों में जलन की शिकायत होती है।



विराट का नंबर वन का ताज खतरों में

न्यूजीलैंड का बल्लेबाज सिर्फ एक अंक पीछे

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली हाल ही में आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर एक बनकर लौटे थे, लेकिन अब उनका यह ताज लंबा नहीं टिकने वाला लगता है। न्यूजीलैंड के धुरंधर बल्लेबाज डेरिल मिशेल बस एक अंक की दूरी पर कोहली को पीछा कर सकते हैं। कोहली के हालिया प्रदर्शन और रैंकिंग अपडेट ने यह दर्शाया है कि तीसरे वनडे मैच में ही नई रैंकिंग तय हो सकती है। विराट कोहली ने अक्टूबर 2025 से अपने वनडे करियर में शानदार वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में नाबाद अर्धशतक से शुरुआत करते हुए, उन्होंने लगातार चार मैचों में 50 से अधिक रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर कोहली ने फिर से नंबर वन का ताज हासिल किया। इस लगातार प्रदर्शन के चलते उनके 785 रेटिंग पॉइंट्स के साथ यह दूसरी बार हुआ है जब उन्होंने 2021 के बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज का स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ कोहली वनडे में 11वीं बार नंबर 1 बल्लेबाज बने और कुल 825 दिनों तक यह मुकाम बनाए रखा - किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए सबसे लंबा रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल फिलहाल विराट कोहली से सिर्फ एक अंक पीछे हैं। मिशेल ने पहले वनडे में 71 गेंदों पर 84 रन बनाए, जिससे वह रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचे। इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 131 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस नजदीकी मुकाबले के चलते तीसरे वनडे का नतीजा ही तय करेगा कि नंबर वन बल्लेबाज कौन होगा।

मुझे हैरानी हुई कि न्यूजीलैंड इतनी आसानी से जीत गया: गावस्कर

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें इस बात पर काफी हैरानी हुई कि राजकोट में दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया और रिविंकार को तीसरे और आखिरी मैच में घरेलू टीम को अपनी टीम कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आजादी नहीं दी। डेरिल मिशेल की नाबाद 131 रनों की पारी की बद्दील न्यूजीलैंड ने राजकोट में दूसरे वनडे में सीरीज बराबर करने वाली जीत हासिल की, क्योंकि मेहमान टीम ने 7 विकेट बाकी रहते 285 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब सीरीज का फैसला इंदौर में होगा। गावस्कर ने जियोस्टार के 'अमूल क्रिकेट लाइव' पर कहा, 'मुझे हैरानी हुई कि न्यूजीलैंड इतनी आसानी से जीत गया, क्योंकि जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, तो सभी को लगा था कि भारत पिच की धीमी गति का फायदा उठा जाएगा। उनके (न्यूजीलैंड के) गेंदबाजों ने सिर्फ स्पिनरों ने ही नहीं, बल्कि सभी ने पिच की धीमी गति का अच्छे से इस्तेमाल किया, ऐसा लगा कि भारत न्यूजीलैंड को लगभग 260 या 270 रनों पर रोक जाएगा। मुझे लगा था कि यह भारत के लिए आसान जीत होगी।' गावस्कर ने मिशेल की तारीफ की कि उन्होंने विल यंग (87) के साथ मिलकर 162 रनों की साझेदारी की जिसने मैच भारत से छीन लिया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने दिखाया कि लगभग 300 रनों के टोटल का पीछा कैसे किया जा सकता है, समय लेकर सेट होने के बाद अपनी स्ट्रोक-मेकिंग क्षमता पर भरोसा करके और विकेटों के बीच दौड़कर।' गावस्कर ने कहा कि सीरीज के फाइनल में भारत पर दबाव होगा और उनके पास यशस्वी जायसवाल जैसे किसी खिलाड़ी को आजमाने की गुंजाइश नहीं है जिन्हें इंदौर मैच में शामिल किया जा सकता था। उन्होंने कहा, '...अगर वे यह मैच जीत जाते, तो उनके पास थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की आजादी होती, शायद उन खिलाड़ियों को मौका देते जो अब तक नहीं खेले हैं। जायसवाल जैसे किसी खिलाड़ी को भी थोड़ा मौका मिल सकता था। यह सब मुश्किल हो सकता था। लेकिन अब वे कोई चॉंस नहीं ले सकते। उन्हें फिर से अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन के साथ खेलना होगा।'

वेस्टइंडीज बोर्ड ने लगा लिया पूरा जोर, निकोलस पूरन ने संन्यास से वापसी के प्रस्ताव पर जो कहा, जानकर हैरान रह जाओगे

नई दिल्ली, एजेंसी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट वेस्टइंडीज की अपनी एक खिलाड़ी से बड़ा झटका लगा है, स्टार खिलाड़ी निकोलस पूरन ने पिछले साल कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंकाया था। बोर्ड चाहता है कि उनका ये धाकड़ खिलाड़ी अपना रिटायरमेंट वापस ले लें और उनके लिए टी20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के क्रिकेट निदेशक माइल्स बासकोम्बे ने इस बात को स्वीकारा है कि निकोलस पूरन से संपर्क किया गया था। बोर्ड चाहता था कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मजबूत टीम के साथ उतरा जाए। माइल्स ने कहा, 'टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज टीम का प्रतिनिधित्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी करें, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया। हमने वापसी की संभावनाओं पर भी बात की, लेकिन निकोलस अपने फैसले पर कायम रहे।' उन्होंने ये भी बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखकर ही पूरन ने संन्यास लिया था।

वेस्टइंडीज को खलेगी निकोलस पूरन की कमी

पूरन टी20 के सबसे घातक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो आते ही बड़े प्रहार करने में माहिर हैं। उनकी फील्डिंग भी लाजवाब है, बतौर विकेटकीपर भी उन्होंने प्रभावित किया है। कुल मिलाकर एक कम्प्लीट पैकेज, लेकिन छोटी उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। कई खिलाड़ियों का इंटरनेशनल क्रिकेट सफर 30 के आस पास शुरू हुआ है, उनमें से एक भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी हैं। लेकिन पूरन ने 29 साल की उम्र में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम गुप सी में शामिल है, इस गुप के सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे।

इंडिया-न्यूजीलैंड: इस भारतीय खिलाड़ी को मिली चैतावनी

● तीसरे मैच की प्लेइंग 11 से कट सकता है पाता

नई दिल्ली, एजेंसी। वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद दूसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में नितीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया, लेकिन वो बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों मोर्चे पर फेल रहे। नितीश ने राजकोट में 21 गेंदों पर 20 रन बनाए और दो ओवर गेंदबाजी की, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए। नितीश रेड्डी को मिली चैतावनी - नितीश के इस असरहीन प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टैन डोशेट ने माना कि कई मौके मिलने के बावजूद वो टीम के भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए हैं। दूसरे मैच में भारत को मिली हार के बाद रयान टैन ने कहा कि हम नितीश के बारे में बात करते रहते हैं कि उसे डेवलप करना है और उसे गेम टाइम देना है, लेकिन जब उन्हें गेम टाइम मिलता है तो वह कुछ खास नहीं कर पाते। 22 साल के इस ऑलराउंडर ने अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से सभी फॉर्मेट में एक संचुरी लगाई है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 10 टेस्ट, 3 वनडे और चार टी20 खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 533 रन बनाए हैं। रयान ने कहा कि रेड्डी को अपने सामने आने वाले मौकों को भुनाना होगा। उन्होंने कहा कि राजकोट में नितीश के पास परफेक्ट मौका था।

एसएस20: काव्या मारन को मिला धुरंधर खिलाड़ी, डेब्यू पर डबल धमाल मचाकर टीम को बनाया नंबर 1

टी20 क्रिकेट की दुनिया एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ियों से भरी है, लेकिन, आईपीएल IPL जैम्स कोल्स ने अपना डेब्यू जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ किया और मुकाबले में अपने नाम की धूम मचा दी। जैम्स कोल्स ने इस मैच में अपने ऑलराउंडर होने के पूरे सबूत दिए, सुपर किंग्स पर उनका कहर सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी बरपा। जैम्स कोल्स ने डेब्यू पर क्या डबल धमाल किया - मुकाबले में सनराइजर्स इस्टर्न के पहले बल्लेबाजी की ओर 20 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन बनाए, टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में छठे नंबर पर उतरे जैम्स कोल्स की भूमिका सबसे बड़ी रही। उन्होंने मैच में अपनी टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए। जैम्स कोल्स ने 34 गेंदों का सामना कर 61 रन बनाए, जिसमें 10 बाउंड्रीज शामिल रही। इसके बाद जब जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स 179 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो जैम्स कोल्स का कहर गेंद से भी बरपा, उन्होंने बल्लेबाजी वाला फॉर्म गेंदबाजी में भी दिखाते हुए 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए।

विराट कोहली पर बयानबाजी: हरभजन सिंह ने संजय मांजरेकर को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। विराट कोहली का नाम आते ही भारतीय क्रिकेट में बहस अपने आप तेज हो जाती है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर के एक बयान ने ऐसी ही चर्चा को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़कर वनडे को इसलिए चुना क्योंकि यह 'खेलने का सबसे आसान फॉर्मेट' है। इस टिप्पणी पर अब पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने न सिर्फ इस सोच का विरोध किया, बल्कि कोहली की महानता और निरंतरता का मजबूती से बचाव भी किया।

हरभजन सिंह का साफ संदेश: क्रिकेट कभी आसान नहीं होता

हरभजन सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मांजरेकर की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में रन बनाना आसान नहीं होता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी भी स्तर पर बल्लेबाजी करना आसान होता, तो हर खिलाड़ी लगातार रन बना रहा होता। हरभजन के मुताबिक, जो खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए, न कि उनके फॉर्मेट को लेकर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। कोहली की निरंतरता और मैच-विनर छवि का बचाव हरभजन ने विराट कोहली को भारत का एक भरोसेमंद मैच-विनर बताते हुए कहा कि उन्होंने हर फॉर्मेट में देश के लिए अहम योगदान दिया है। चाहे कोहली एक फॉर्मेट खेलें या तीनों, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता।



ऑपरेशन स्वदेश: ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की तैयारी

नई दिल्ली। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन और अशांति के बीच केंद्र सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए 'ऑपरेशन स्वदेश' शुरू कर दिया है। सरकार ने इस ऑपरेशन के तहत विशेष फ्लाइट्स के माध्यम से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन का पहला विमान आज तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। ईरान में इस समय लगभग 10 हजार भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से छात्र, कारोबारी और प्रवेश प्रामिल हैं। इनमें से करीब 2500 से 3000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए हुए हैं। इनमें से अधिकांश को अब सुरक्षित तरीके से भारत लौटने के लिए तैयार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने ईरान की यात्रा से फिलहाल बचने की सलाह जारी की है और भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने एक बयान में बताया कि सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। भारतीय दूतावास ने उनकी पर्सनल डिटेल्स और पासपोर्ट इकट्ठा कर लिए हैं। छात्रों को पहले बैच में उड़ान के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे तक तैयार रहने को कहा गया है। दूतावास और JKSA ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी छात्र इस प्रक्रिया में छूट न जाए। पहले बैच में गोलेस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के



कुछ स्टूडेंट्स शामिल होंगे। ऑपरेशन की तैयारी के तहत छात्रों की सुरक्षा और उन्हें एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं। फाइनलिस्ट देर रात तक जारी की जाएगी ताकि सभी छात्रों को समय पर फ्लाइट में शामिल किया जा सके। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने लगातार छात्रों और उनके परिवारों को स्थिति से अवगत कराया है। छात्रों को किसी भी तरह की अपात स्थिति के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि फ्लाइट्स में पर्याप्त मेडिकल और सुरक्षा स्टाफ भी मौजूद रहेगा। ईरान में प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पर हिंसा की भी घटनाएँ सामने आ रही हैं। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से भारत लाया जाए। छात्रों और अन्य नागरिकों की वापसी को लेकर व्यापक रूप से सभी प्रशासनिक तैयारियों की गई हैं। इस ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने यह संदेश भी दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अधिकार से परिणाम तक: -मनरेगा के बाद शिक्षा-खाद्य सुरक्षा कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार यूपीए सरकार के दौर में बने सामाजिक अधिकारों से जुड़े बड़े कानूनों की दोबारा समीक्षा और सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में बदलाव के बाद अब शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) में सुधार की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार का मानना है कि किसी योजना या सुविधा को केवल कानूनी अधिकार बना देना काफी नहीं है, बल्कि उसका ज़मीन पर सही और प्रभावी तरीके से लागू होना ज़रूरी है। सरकार द्वारा की गई अंतरिक समीक्षा में यह बात सामने आई है कि शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास जैसे पांच बेहद अहम क्षेत्रों में बने अधिकार आधारित कानूनों से अपेक्षित नतीजे पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसका असर सरकार की विश्वसनीयता और योजनाओं की प्रभावशीलता पर भी पड़ा है। इसी वजह से अब सरकार इन कानूनों को अधिक परिणाम आधारित और जवाबदेह बनाना चाहती है।

सरकार के तीन बड़े टारगेट- सरकार ने साफ किया है कि सुधार की पूरी प्रक्रिया तीन मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित होगी— समय-सीमा के साथ 100% कवरेज; सरकार चाहती है कि हर योजना के लिए तय समय-सीमा में पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हो। यानी जो भी व्यक्ति पात्र है, वह किसी भी हालत में योजना से बाहर न रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म और रियल टाइम मॉनिटरिंग; योजनाओं के क्रियान्वयन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा, गड़बड़ियों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। हर व्यक्ति की पहचान और पंजीकरण; सभी लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी पंजीकरण

अभियान चलाने की तैयारी है। आधार और अन्य डिजिटल पहचान साधनों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।



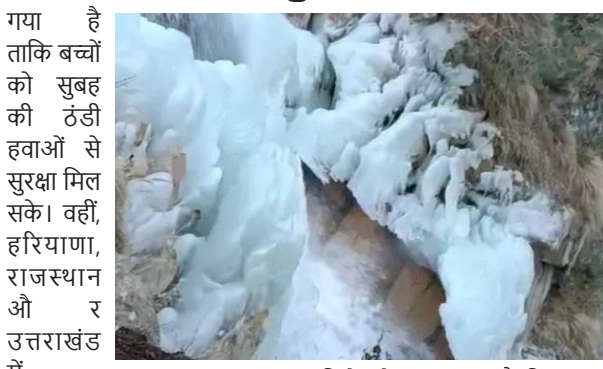
सुरक्षा कानून में क्यों ज़रूरी है बदलाव? परामर्श प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय बने अधिकार आधारित कानूनों में तीन बड़ी कमियां रहीं— कानून बनने के बाद भी क्रियान्वयन कमजोर रहा, राज्यों के बीच अमल में असमानता, लाभार्थियों की सटीक पहचान और निगरानी का अभाव, शिक्षा का अधिकार कानून के बावजूद आज भी देश

में बड़ी संख्या में बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। स्कूलों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और सीखने के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। इसी तरह, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत करोड़ों लोगों को सस्ता या मुफ्त अनाज मिला, लेकिन लीकेज, फर्जी राशन कार्ड और अपात्र लोगों को लाभ जैसी समस्याएं लगातार सामने आती रहीं।

क्या है खाद्य सुरक्षा कानून? भारत में खाद्य सुरक्षा से जुड़ा प्रमुख कानून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। यह कानून 2013 में लागू हुआ था और इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मिड-डे मील और आंगनवाड़ी सेवाओं को कानूनी ढांचा दिया गया। इसके अलावा खाद्य मानकों और गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 भी लागू है, जिसके तहत FSSAI काम करता है। सरकार अब इन कानूनों के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी व तकनीक आधारित बनाना चाहती है। **पहले नियमों से, फिर ज़रूरत पड़ी तो कानून से सुधार-** सरकारी की योजना है कि पहले चरण में नियमों और सरकारी आदेशों के जरिए सुधार किए जाएं। अगर इसके अपेक्षित बदलाव नहीं आता है, तो संसद में नए संशोधन विधेयक या नए कानून भी लाए जा सकते हैं। इसी कड़ी में सरकार यह भी विचार कर रही है कि आवास के अधिकार को भी कानूनी अधिकार बनाया जाए, ताकि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन के लिए पक्का घर मिल सके।

हरियाणा-पंजाब-उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और जमे झरने; स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

नई दिल्ली। देश के उत्तरी हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दो साल का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। सर्द हवाओं ने लोगों की खासी परेशानियां बढ़ा दी हैं, खासकर सुबह और रात के समय में। उत्तराखंड के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज और भी सख्त हो गया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क, भागीरथी नदी और जाड़ गंगा झरना पूरी तरह से जम चुके हैं। इन झरनों और नदियों के जमे पानी की तस्वीरें स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। बर्फबारी और जमा पानी की वजह से पहाड़ी मार्गों पर यातायात थोड़ी मुश्किलों भरी हो सकती है। पंजाब में भी ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। राज्य में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्कूलों का समय बदल दिया



गया है ताकि बच्चों को सुबह की ठंडी हवाओं से सुरक्षा मिल सके। वहीं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में अत्यधिक ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी दो दिन के लिए स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। दिल्ली में हालांकि पांच दिन की शीतलहर के बाद थोड़ी राहत मिली है। शहर का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले दिन की तुलना में लगभग दो डिग्री अधिक है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद सुबह के समय लोगों को अभी भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हुई। 88% उड़ानों को संचालन में एक से उड़ें घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। रनवे की अधिकतम विजिबिलिटी 900 मीटर और न्यूनतम विजिबिलिटी 200 मीटर के बीच रही। मौसम

माचडो ने ट्रम्प को नोबेल मेडल भेंट किया, भरोसा जताया पर समर्थन नहीं मिला

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। यह मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि यह ट्रम्प और किसी भी वेनेजुएला के नेता के बीच पहली आमने-सामने बैठक थी। मचाडो वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विरोधी नेता मानी जाती हैं और देश में उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार चर्चा में रही है। मुलाकात के दौरान मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया।



बेटक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मचाडो ने कहा, "मुझे लगता है कि आज हमारे देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।" उन्होंने अपने इस कदम को वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बेहतर समझ और सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक संकेत बताया। हालांकि, उन्होंने इस दौरान किसी भी तरह की और जानकारी साझा नहीं की, जैसे कि ट्रम्प ने मेडल स्वीकार किया या नहीं। व्हाइट

हाउस ने भी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया। इसके बावजूद, मचाडो ने व्हाइट हाउस से बाहर निकलते समय अपने समर्थकों से स्पिनश में कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रम्प पर भरोसा कर सकते हैं।" यह बयान दर्शाता है कि मचाडो ट्रम्प के प्रति अपनी उम्मीद और विश्वास व्यक्त करना चाहती हैं। हालांकि, असलियत यह है कि ट्रम्प ने मचाडो को वेनेजुएला का नई राष्ट्रपति या वैकल्पिक नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है। फिलहाल वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज के साथ ही काम कर रहे हैं और मादुरो विरोधी गुट को सौंपे नहीं दिया है। इस मुलाकात से यह संकेत ज़रूर मिलता है कि वेनेजुएला के राजनीतिक विवाद और अमेरिका की विदेश नीति में इस मुद्दे की अहमियत लगातार बनी हुई है।

भाजपा बोली- सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को सिखाया सबक, बंगाल विधानसभा चुनाव में हार तय?

कोलकाता। बंगाल में I-PAC रेड मामले को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसे भाजपा ने अपनी राजनीतिक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में पेश किया है। I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस फैसले को भाजपा ने सीधे राजनीतिक लाभ के रूप में देखा है। भाजपा विधायक और नेता अग्रिमित्रा पॉल ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की झूठी राजनीति अब उजागर हो गई है और उनका शासन की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। अग्रिमित्रा पॉल ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और उसके पहले की वामपंथी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए रॉडिंग्ग, बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं का सहारा लिया। लेकिन इस बार बंगाल की जनता और प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं और भविष्य में और नाम हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उनका कहना था कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए ज़रूरी था और अब बंगाल में कोई भी राजनीतिक दल ऐसी गड़बड़ी का लाभ नहीं उठा पाएगा। भाजपा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री पद



की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई थी और अब सच्चाई धीरे-धीरे सामने आ रही है। अग्रिमित्रा पॉल ने कहा कि अदालत ने इस मामले में निष्पक्षता का परिचय दिया और राज्य में भ्रष्टाचार और सत्ता का गलत इस्तेमाल उजागर हुआ। उनका यह भी कहना था कि भाजपा इस फैसले का स्वागत करती है और भविष्य में बंगाल विधानसभा चुनाव में यह स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आएगी। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक असर भी अवश्य होगा। चुनावी वर्ष में ऐसा फैसला TMC के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भाजपा इस चुनावी रणनीति में इस्तेमाल कर सकती है। भाजपा का जोर है कि यह साबित हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीति पारदर्शी नहीं थी और अब जनता के सामने सच्चाई रखी जाएगी। I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि कानून का शासन पहले की तरह किसी भी राजनीतिक दबाव या पार्टी के प्रभाव से प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जवाब मांगा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो।

इंदौर में दूषित पानी से 24 मौतें: -राहुल गांधी का दौरा सीमित, बैठक को प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी

भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण हुई घटनाओं ने शहर की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, अब तक इस दूषित पानी से प्रभावित होने वाले कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दलों के लिए गंभीर चुनौती पेश की है। ऐसे में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार, 17 जनवरी को इंदौर का दौरा करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवारों और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात करना है, लेकिन प्रशासन ने उनके प्रस्तावित व्यापक कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशभर के पार्षदों, महापौरों, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इस बैठक में लगभग एक हजार लोगों की उपस्थिति की योजना बनाई गई थी। बैठक का आयोजन अभय प्रशाल और आनंद मोहन माधुर सभागार में किया जाना था, लेकिन जिला प्रशासन ने भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति और संबंध सार्वजनिक सुरक्षा खतरों को देखते हुए इस बैठक को मंजूरी नहीं दी। कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले ने बताया कि प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण बैठक को रद्द



करना पड़ा है। उन्होंने कहा, "हमने प्रशासन से अनुमति लेने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के कारण अनुमति नहीं दी गई। अब राहुल गांधी का दौरा सीमित कार्यक्रम तक ही रहेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी अब केवल सीधे पीड़ित परिवारों और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत बॉम्बे हॉस्पिटल से होगी। यहां व दूषित पानी के कारण बीमार हुए मरीजों और उनके परिजनों से मिलेंगे। कांग्रेस ने यह बताया कि अस्पतालों में मिलने का उद्देश्य मरीजों की हालत का जायजा लेना और सरकार से तत्काल राहत देने की मांग करना है। इसके बाद राहुल गांधी भागीरथपुरा जाएंगे, जहां वे उन परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिनके परिजन इस दूषित पानी से हुई घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र

ईरान की ओर बढ़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन: मध्य पूर्व में सैन्य तनाव बढ़ा

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। यह रिपोर्ट ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य तनाव की ओर संकेत करती है। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच, अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर-पावर्ड है और दुनिया के सबसे बड़े तथा सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक माना जाता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस निर्णय के पीछे ईरानी एयरस्पेस के अचानक बंद होने की घटना है, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। स्ट्राइक ग्रुप पहले चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात था, लेकिन अब इसे मध्य पूर्व में संभावित खतरों पर सैन्य ज़रूरतों के मद्देनजर भेजा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तैनाती एक तरह से क्षेत्रीय दबाव बनाने और सैन्य विकल्पों को तैयार रखने की



रणनीति का हिस्सा हो सकती है। USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ आने वाले स्ट्राइक ग्रुप में कई युद्धपोत, कूजर और विमान शामिल हैं, जो किसी भी सैन्य आपरेशन को तुरंत सक्षम बनाने में मदद करते हैं। मिडिल ईस्ट पहुंचने में इस समूह को लगभग एक हफ्ते का समय लग सकता है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्लेषकों ने नोट किया है कि अमेरिका ने पहले भी वेनेजुएला में हमले से पहले इसी तरह की सैन्य घेराबंदी की थी। इसका मतलब है कि अमेरिकी कदम संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी या किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए चेतावनी का संकेत भी हो सकता है। इस स्थिति से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की संभावना है, और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी सैन्य टकराव से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

पाकिस्तान का दावा: भारत के साथ संघर्ष के बाद JF-17 फाइटर जेट्स की अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ी

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान ने हाल ही में कहा है कि भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद उनके फाइटर जेट्स की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रेडियो पाकिस्तान को बताया कि कई देश अब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन प्रकार के जेट्स की डिमांड बढ़ी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि विशेष रूप से JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की मांग बढ़ रही है। JF-17 पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रयास से विकसित लड़ाकू विमान है, जो कम लागत में प्रभावी हथियार प्रणाली प्रदान करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विमान को खरीदने में बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसी मुस्लिम देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान के लिए फाइटर जेट्स की लड़ाकू क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। JF-17 थंडर



जेट्स आधुनिक हथियार प्रणाली, राडार और मिसाइल क्षमताओं से लैस है, जो उन्हें क्षेत्रीय संघर्षों में प्रभावी बनाते हैं। पाकिस्तान का यह दावा इस बात का संकेत भी है कि उनके विमान निर्यात के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग को मजबूती देने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। JF-17 की निर्यात क्षमता पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में मदद कर सकती है। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य रहे कि इस तरह के दावे अक्सर राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से पेश किए जाते हैं। वास्तविक सौदों और समझौतों की पुष्टि तब ही हो पाएगी जब संबंधित देशों के रक्षा मंत्रालय या सरकारी एजेंसियों द्वारा आधिकारिक घोषणा की जाए। फिलहाल, पाकिस्तान के पीएम का यह बयान एक संकेत है कि देश अपने विमान उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना चाहता है।